अक्टूबर- 2023

मूल्य–10/–

सोशल वेव

वर्ष-01 अंक-03

हिन्दी मासिक पत्रिका

विराट सांस्कृतिक चेतना ...

महिला सशक्तिकरण की दिशा में

महत्वपूर्ण कदम

डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए संपर्क करे, 7007789842

http://www.darjeelingteagarden.com

सोशल वेव

हिन्दी मासिक पत्रिका

वर्ष- 01 अंक- 03 अक्टूबर- 2023

सम्पादक

संध्या राय

प्रबन्ध सम्पादक

देवेंद्र वर्मा

mi सम्पादक

अमित राय

संवाददाता

vcjh'k xkLokeh ¼iVuk½
cjdr vyh ¼xkj[kij½
lR;Un dekj ¼y[kuÅ½
vfHk"kd jk; ¼egjktxat½

विधि सलाहकार

v'ouh JhokLro] ,MoksdsV
dfiy no f=ikBh] ,MoksdsV

foKkiu çHkkjh

vfHk"kd xlrk

ग्राफिक्स

noUn flg

सम्पादकीय कार्यालय

665ch] xxk Vkyk] utnhd tkudh
fcfYMx eVfj;y] ck'kkjrij
oLV]xkj[kij] mUkj çn'k 273003

TITLE CODE :- UPHIN51018

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक संध्या राय द्वारा फाइन ऑफसेट प्रिंटर्स मदरसा हुसैनिया बिल्डिंग बक्सीपुर से मुद्रित एवं न्यू कॉलोनी झरना टोला कूड़ाघाट से प्रकाशित।

नोट- पत्रिका से सम्बन्धित सभी वाद-विवाद गोरखपुर जिला न्यायालय के अन्तर्गत मान्य होगे ।

16
महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

04
क्या राजनीति में स्वच्छता का मोदी जादू चलेगा?

10
भाजपा को दोबारा सत्ता में लाने के लिए...

26
भारत में राष्ट्रवादी राजनीति ही अब सभी दलों की नियति

32
आलिया का धमाकेदार हॉलीवुड डेब्यू

सम्पादक की कलम से...

बचाव की तैयारी

संध्या राय

सिक्किम की तीस्ता नदी में तबाही की बाढ़ आई है। इस बाढ़ में सेना के 23 जवानों के लापता होने की खबर ने चिंता बढ़ा दी है। अचानक आई बाढ़ से भारी तबाही हुई है। अब प्रभावित इलाकों में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। सिक्किम की तीस्ता नदी में मंगलवार रात को अचानक बाढ़ आने और सेना के 23 जवानों के लापता होने की खबर चिंतित करने वाली है। इस फ्लैश फ्लड के कारण जगह-जगह इन्फ्रास्ट्रक्चर का भी काफी नुकसान हुआ है। सड़कें तो टूटी ही हैं, सैन्य प्रतिष्ठानों को भी नुकसान पहुंचने की खबरें हैं। अभी स्वाभाविक ही सबसे ज्यादा ध्यान लापता सैनिकों की तलाश करने और यह सुनिश्चित करने पर दिया जा रहा है कि जहां भी जरूरी हो जल्द से जल्द मदद उपलब्ध करवाई जाए ताकि इस प्राकृतिक आपदा के चलते किसी के जान गंवाने की नौबत न आए। लेकिन इसके बाद इस पूरे क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान का भी जायजा लेकर उन्हें जल्द से जल्द पुरानी स्थिति में लाना होगा। उत्तरी सिक्किम का यह इलाका भारत-नेपाल सीमा के करीब पड़ता है। हालांकि फ्लैश फ्लड का मूल कारण बादल फटना है, लेकिन कई वजहें रहीं जिनसे यह हादसा अधिकाधिक गंभीर रूप लेता गया। बादल फटने की यह घटना उत्तर सिक्किम के चुंगथाम इलाके में स्थित ल्होनक झील के ऊपर हुई। यह झील ल्होनक ग्लेशियर पर बनी है। बादल फटने के बाद पानी के तेज बहाव के चलते लेक की दीवारें टूट गईं और भारी मात्रा में मलबे के साथ पानी तीस्ता में आया, जिससे नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया। हालांकि बचाव और राहत कार्यों को लेकर सिक्किम सरकार के साथ पश्चिम बंगाल सरकार का तंत्र भी सक्रिय हो गया है और सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इस संबंध में गौर करने वाली एक बात यह भी है कि आपदा प्राकृतिक जरूर है, लेकिन पूरी तरह अप्रत्याशित नहीं कही जा सकती। ल्होनक झील इस क्षेत्र की 14 उन ग्लेशियल लेक्स में शामिल है, जिन्हें पहले से ही संवेदनशील माना जा रहा है। ग्लोबल वॉर्मिंग के प्रभावों से पिघल रहे ल्होनक ग्लेशियर का पानी इसी झील में जमा हो रहा था, जिससे इसका क्षेत्रफल लगातार बढ़ता जा रहा था। इसी साल मार्च महीने में संसद में पेश की गई एक रिपोर्ट में बताया गया था कि हिमालय के तमाम ग्लेशियर अलग-अलग दर से, लेकिन तेजी से पिघल रहे हैं और इस वजह से हिमालय की नदियां किसी भी समय बड़ी प्राकृतिक आपदा का कारण बन सकती हैं। यह सही है कि ग्लोबल वॉर्मिंग वैश्विक मसला है और किसी एक देश की सरकार अकेले अपने बूते इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी बड़े और संवेदनशील ग्लेशियरों की स्थिति पर लगातार नजर रखते हुए संभावित हादसों से निपटने की तैयारी जरूर की जा सकती है। इन हादसों के दायरे में आने वाले इलाकों के लोगों को भी अपेक्षाकृत ज्यादा जागरूक रखा जा सकता है। इन उपायों से हादसे भले न टलें लेकिन उनसे होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

गाजा हमले के बाद जॉर्डन में बाइडेन का शिखर सम्मेलन रद्द

व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मध्य पूर्व यात्रा का जॉर्डन हिस्सा रद्द कर दिया गया है। उन्हें बुधवार को जॉर्डन, मिस्र और फिलिस्तीनी प्राधिकरण के नेताओं के साथ अम्मान में एक शिखर सम्मेलन में शामिल होना था, लेकिन जॉर्डन ने घोषणा की कि वह गाजा सिटी अस्पताल पर बमबारी के बाद बैठक को रद्द कर रहा है। मंगलवार को हुये इस हमले में सैकड़ों लोग मारे गए हैं। इज़राइल ने कहा है कि विस्फोट के लिए फ़िलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के एक रॉकेट का मिसफायर ज़िम्मेदार था, लेकिन अरब दुनिया के अधिकांश लोगों ने इज़राइल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) को दोषी ठहराया था। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने एक बयान में कहा कि अम्मान शिखर सम्मेलन

को रद्द करने का निर्णय जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला के साथ बाइडेन के परामर्श के बाद और अस्पताल विस्फोट के बाद फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अध्यक्ष महमूद अब्बास द्वारा घोषित 'शोक के दिनों' के आलोक में किया गया था। व्हाइट हाउस के अधिकारी ने कहा कि बाइडेन ने किंग अब्दुल्ला को "गाजा के अस्पताल पर हमले में मारे गए निर्दोष लोगों के लिए अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की, और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।" उन्होंने किसी विशेष पक्ष को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया। इस बीच अमेरिका यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि हमला किसने किया था। व्हाइट हाउस के अधिकारी ने कहा बाइडेन जल्द ही इन नेताओं के साथ व्यक्तिगत रूप से परामर्श करने के लिए उत्सुक हैं और आने वाले दिनों में उनमें से प्रत्येक के साथ नियमित रूप से और सीधे तौर पर जुड़े रहने पर सहमत हुए हैं। ■

क्या राजनीति में स्वच्छता का मोदी जादू चलेगा?

भारत की पहचान एक अरब से अधिक भूखे पेटों वाले देश के रूप में रही है, लेकिन अब, भारत को एक अरब से अधिक उम्मीदों से भरे दिमाग, दो अरब से अधिक कुशल हाथों और करोड़ों युवाओं के देश के रूप में देखा जा रहा है। ऐसी स्थितियों में मोदी के नाम पर मांगे जा रहे वोट उन्हें ऐतिहासिक जीत दे तो कोई आश्चर्य नहीं है।

ललित गर्ग

देश में स्वच्छता अभियान से ज्यादा जरूरी हो गया राजनीतिक स्वच्छता अभियान। क्योंकि आजादी के अमृतकाल को अमृतमय बनाने के लिये राजनीति का शुद्धिकरण यानी अपराध एवं भ्रष्टाचारमुक्त होना अपेक्षित है। आज कौन-सी पार्टी है जो सार्वजनिक जीवन में शुचिता का पालन कर रही है? शोचनीय बात यह है कि अब भ्रष्टाचार, आतंकवाद एवं साम्प्रदायिकता को पोषित करने वाले एवं देशविरोधी राजनीति के दोषी शर्मसार भी नहीं होते। इस तरह का राजनीतिक चरित्र देश के समक्ष गम्भीर समस्या बन चुका है। राजनीति की बन चुकी मानसिकता और भ्रष्ट आचरण ने

पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव इसी साल के अंत में होने हैं और इसके बाद अगले वर्ष लोकसभा चुनाव का बिगुल बज उठेगा। ऐसे दौर में राजनीति में सुधार की कोरी बातें ही नहीं बल्कि संकल्पित होने का वक्त आ गया है। यह वक्त देखा जाए तो चुनाव सुधार एवं राजनीति में नैतिक मूल्यों को बल देने का बिगुल बजाने का है। चुनाव में अच्छे एवं ईमानदार, लोग चुन कर आएं इसके लिए राजनीति में अपराधियों का प्रवेश तो रोकना ही होगा, वंशवाद, जातिवाद, धनबल व बाहुबल जैसी राजनीति में घुस आई गंदगी को साफ करने के लिए 'जागरूकता की झाड़ू' को उठाना ही होगा। अभी तो आम धारणा यही बनती जा रही है कि ईमानदारी के बलबूते चुनाव जीतना आसान नहीं है। लेकिन आगामी चुनावों में इस धारणा को बदल देना है।

पूरे लोकतंत्र और पूरी व्यवस्था को प्रदूषित कर दिया है। स्वहित और स्वयं की प्रशंसा में ही लोकहित है, यह सोच हमारी राजनीति मं घर कर चुकी है। यह रोग राजनीति को इस तरह जकड़ रहा है कि हर राजनेता लोक के बजाए स्वयं के लिए सब कुछ कर रहा है। अधिकतर राजनीतिकों का मकसद बस किसी तरह चुनाव जीतना और सत्ता में जाना हो गया है। चुनाव जीतने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया जाता है, और सत्ता में आने पर पैसा बनाने के सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नौ वर्ष पहले स्वच्छता अभियान छेड़ा, जिसका व्यापक असर हुआ। अब देश में दूषित होती राजनीति में स्वच्छता अभियान शुरू करने की पहल करने की अपेक्षा है।

पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव इसी साल के अंत में होने हैं और इसके बाद अगले वर्ष लोकसभा चुनाव का बिगुल बज उठेगा। ऐसे दौर में राजनीति में सुधार की कोरी बातें ही नहीं बल्कि संकल्पित होने का वक्त आ गया है। यह वक्त देखा जाए तो चुनाव सुधार एवं राजनीति में नैतिक मूल्यों को बल देने का बिगुल बजाने का है। चुनाव में अच्छे एवं ईमानदार, लोग चुन कर आएं इसके लिए राजनीति में अपराधियों का प्रवेश तो रोकना ही होगा, वंशवाद, जातिवाद, धनबल व बाहुबल जैसी राजनीति में घुस आई गंदगी को साफ करने के लिए 'जागरूकता की झाड़ू' को उठाना ही होगा। अभी तो आम धारणा यही बनती जा रही है कि ईमानदारी के बलबूते चुनाव जीतना आसान नहीं है। लेकिन आगामी चुनावों में इस धारणा को बदल देना है। चुनाव सुधारों को लेकर उच्चतम न्यायालय से लेकर चुनाव आयोग तक की सिफारिशें एवं सुझाव हर बार हवा होते रहे हैं। उन पर अमल करने की परवाह किसी को नहीं होती। ठीक इसी तरह राजनीति के शुद्धिकरण का संकल्प भी हर चुनाव में खारिज होता रहा है, लेकिन कब तक? प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति में नैतिक एवं ईमानदार चेहरा को प्रोत्साहन दिया है। ऐसा करके उन्होंने यह भी जता दिया कि राजनीति की चली आ रही परिभाषाएं अब बदलने लगी है। अब मोदी के नाम पर उन राज्यों में चुनाव जीतने के कीर्तिमान स्थापित हुए है, जहां चुनाव जीतना किन्हीं खास धनबल, बाहुबल एवं अपराधिक तत्वों के नाम लिखे हुए थे।

बात लोकसभा चुनाव की नहीं, विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनावों की है कि मोदी के नाम पर ये चुनाव इतने सफल क्यों एवं कैसे हो रहे हैं? पार्टी के कद्दावर नेता, जिनके बिना राज्य में चुनाव जीतना असंभव माना जाता रहा है, उन नेताओं के नाम की बजाय मोदी के नाम पर वोट मांगने की परम्परा मजबूत एवं सफल होती जा रही है, क्योंकि मोदी एक प्रतीक है विकास का, मूल्यों का, जन समस्याओं के समाधान का। गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान पहले कार्यकाल में नरेंद्र मोदी ने हिंदू हृदय सम्राट की छवि बनाई। दूसरे कार्यकाल के बाद विकास, शांति एवं सौहार्द का प्रतीक बन गए। गुजरात मॉडल का प्रचार इतना जबर्दस्त रहा कि अन्य राज्यों में भी इसकी चर्चा होने लगी। बिहार-यूपी जैसे सुदूर क्षेत्रों के लोग भी गुजरात मॉडल की बात करने लगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद ब्रांड मोदी और भी मजबूत हो गया। 2019 लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद मोदी अपराजेय दिखने लगे। 2024 के चुनाव में भी विपक्षी गठबंधन इंडिया के सामने यही सवाल खड़ा है कि नरेंद्र मोदी को चुनौती देने वाला नेता कौन होगा? इंडिया के सामने नेता घोषित करने की दोहरी चुनौती है। अगर चुनाव से पहले इंडिया का नेता चुन लिया गया, तो उसकी तुलना नरेंद्र मोदी से होगी। अगर नहीं चुना गया तो विपक्ष बिखरा ही दिखाई देगा।

नरेंद्र मोदी ने अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आलोचना की परवाह किए बगैर कई ऐस देशहित के बड़े फैसले लिए, जिनसे न सिर्फ विपक्ष बल्कि भारत की जनता भी चौंक गई। नोटबंदी, उड़ी हमले के बाद पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक,

पाकिस्तान समर्थित कश्मीर में एयर स्ट्राइक की विपक्ष ने आलोचना की, कश्मीर में राजनीतिक स्थिति में भारी बदलाव करते हुए विधानसभा सहित केंद्रशासित प्रदेश बना दिया तथा लद्दाख को भी जम्मू कश्मीर से अलग करके उसे भी अलग केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। इन निर्णयों से कश्मीर के नेता बौखला गये, भारी विरोध किया, मगर नरेंद्र मोदी ने इस पर कभी अफसोस नहीं जताया। कोरोना की दूसरी लहर में लॉकडाउन के फैसला भी विरोधियों के निशाने पर रहा। सीएए को लेकर भी काफी हो-हल्ला हो चुका है। 2024 के चुनाव में जाने से पहले नरेंद्र मोदी चौंकाने वाला फैसला ले सकते हैं। 18 सितंबर 2023 से संसद का विशेष सत्र में नारी वन्दन विधेयक पारित किया। वैसे चुनाव से पहले राम मंदिर का उद्घाटन होना तय है। मोदी की साफ-सुथरी छवि एवं भ्रष्टाचारमुक्त राजनीति का ही परिणाम है कि विपक्ष की अनेक कोशिशों के बावजूद वे उनके खिलाफ कोई एक भी मुद्दा नहीं खोज पाये। केंद्र की मोदी सरकार ने राजनीति में बड़े बदलाव भ्रष्टाचार और करप्शन के मुद्दे पर किए हैं। 1989 के चुनाव में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बोफोर्स का मुद्दा उछाला था। बोफोर्स से जुड़े कांग्रेस नेताओं के नाम पर उन्होंने चुनाव जीता। नरसिंह राव की सरकार भी घोटालों के घिरी थी, जिसका फायदा बीजेपी समेत विपक्ष को मिला था। 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार कोयला घोटाले, 2जी और कॉमनवेल्थ घोटाले की चर्चा के बीच चुनाव में गई थी, नतीजा कांग्रेस चुनाव हार गई।

कांग्रेस ने भी लगातार नरेंद्र मोदी सरकार को घोटाले पर घेरने की कोशिश की, मगर ब्रांड मोदी के सामने उसे चुनावी मुद्दा नहीं बना पाई। 2019 में कांग्रेस ने राफेल में करप्शन का मुद्दा उठाया। नोटबंदी में करप्शन के आरोप लगाए। अडानी और अंबानी के मुद्दे को चुनाव में उठाया, मगर मोदी मैजिक के सामने सारे वार फेल हो गए। 2024 से पहले कांग्रेस फिर अडानी और अंबानी के इर्द-गिर्द घूम रही है। इससे उलट इंडिया के कई नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच चल रही है। देश में आशावाद और सकारात्मकता का माहौल है, लोग जी20, चंद्रयान और

बात लोकसभा चुनाव की नहीं, विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनावों की है कि मोदी के नाम पर ये चुनाव इतने सफल क्यों एवं कैसे हो रहे हैं? पार्टी के कद्दावर नेता, जिनके बिना राज्य में चुनाव जीतना असंभव माना जाता रहा है, उन नेताओं के नाम की बजाय मोदी के नाम पर वोट मांगने की परम्परा मजबूत एवं सफल होती जा रही है, क्योंकि मोदी एक प्रतीक है विकास का, मूल्यों का, जन समस्याओं के समाधान का। गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान पहले कार्यकाल में नरेंद्र मोदी ने हिंदू हृदय सम्राट की छवि बनाई।

अर्थव्यवस्था की सफलता का उत्सव मना रहा है, 2024 में एक बड़ी जीत के लिए आश्वस्त दिखते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति को अपराध एवं भ्रष्टाचारमुक्त करने की ठानी है तो यह समय आम मतदाता के जागरूक एवं सर्तक होने का भी है। राजनीति में सुधार चाहने वालों के लिए यह घर बैठने का समय नहीं है। राजनीति में नैतिकता को लेकर उठ रहे सवालों के बीच चुनाव सुधारों की कोरी बातें ही नहीं बल्कि उन पर अमल लाने की भी जरूरत है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टियों की है कि वे ठोक-बजाकर उम्मीदवारों का चयन करें। चिंता इस बात की है कि जनता ही दागियों को वोट देकर सत्ता में लाती है। इसलिए प्रमुखतः राजनीति में स्वच्छता के लिए कदम उसे भी बढ़ाने होंगे। वर्ना मोदी का करिश्मा एवं जादू तो अपना असर दिखायेगा ही, क्योंकि उनके पास सत्य एवं नैतिकता का बल है। मोदी ने ही देश पर लगे गरीब होने के दंश को हटाने की सार्थक पहल की है, उन्हीं के शब्दों में लंबे वक्त तक, भारत की पहचान एक अरब से अधिक भूखे पेटों वाले देश के रूप में रही है, लेकिन अब, भारत को एक अरब से अधिक उम्मीदों से भरे दिमाग, दो अरब से अधिक कुशल हाथों और करोड़ों युवाओं के देश के रूप में देखा जा रहा है। ऐसी स्थितियों में मोदी के नाम पर मांगे जा रहे वोट उन्हें ऐतिहासिक जीत दे तो कोई आश्चर्य नहीं है। ■ ✔

झारखंड में दो रुपए की बख्शीश से हुई थी कोयला मजदूरों के बोनस की शुरुआत

रमन रावी

बात कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण के पूर्व की है। तब निजी खदान मालिक मिठाई के डिब्बे के साथ कोयला मजदूरों को दुर्गा पूजा के अवसर पर डेढ़-दो रुपए की बख्शीश दिया करते थे। राष्ट्रीयकरण के बाद उसी बख्शीश ने बोनस (प्रॉफिट लिंक्ड रिवॉर्ड) का रूप ले लिया। आज इसका स्वरूप यह है कि एक-एक कोयला कर्मचारी को 85-85 हजार रुपए तक बोनस देने की घोषणा की गई है।

धनबाद कोयला क्षेत्र के इंटक के पुराने नेता एके झा कहते हैं कि निजी खदान मालिक दुर्गा पूजा के अंतिम समय यानी सप्तमी-अष्टमी को बख्शीश का भुगतान करते थे। इसकी वजह यह थी कि मजदूर अपने गांव नहीं चले जाएं। तब कोयला खदान में कोई काम करना नहीं चाहता था। मैनुअल खनन के कारण ज्यादा हादसे होते थे। वही लोग कोयला खदानों में काम करते थे जिनके पास पेट पालने का कोई विकल्प नहीं था। तब ज्यादातर खदान मालिक गुजराती थे। बिहार तथा यूपी के पूर्वांचल इलाके से कोयला खनन के लिए मजदूरों को लाते थे। आज भी बिहार-यूपी के क्षेत्रवार मजदूरों की कॉलोनी धनबाद के पुराना धौड़ा कोलियरी क्षेत्रों में है। तब स्थायी प्रकृति की नौकरी भी नहीं थी। फावड़ा और टोकरी से कोयले की खुदाई और ढुलाई होती थी।

बोनस से झारखंड के बाजार में उत्साह

कोयला कर्मचारियों को बोनस देने की घोषणा से बाजार में उत्साह है। कोल इंडिया एवं अनुषंगी कंपनियां अपने 2.27 लाख कोयला कर्मियों के बीच 21 अक्टूबर तक बोनस के रूप में 1900 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। झारखंड में सबसे ज्यादा बोनस का 700 करोड़ रुपए आएगा।

यूं तो बोनस कई कंपनियां मसलन सेल, टाटा आदि भी देती हैं लेकिन झारखंड में कोयले का बोनस सबसे ज्यादा होता है। झारखंड के तकरीबन हर इलाके में कोयलांचल है। बीसीसीएल के कारण धनबाद सबसे सघन कोयला क्षेत्र है। वहीं सीसीएल की झारखंड के छह जिले में खदानें हैं। ईसीएल का झारखंड में निरसा कोयला क्षेत्र से लेकर देवघर और राजमहल में खदानें हैं। कुल मिलाकर झारखंड के लगभग 80 हजार कोयला कर्मियों को बोनस का भुगतान होगा। ■

उत्तर प्रदेश का वातावरण अशांत करने का

षड्यंत्र आखिर कौन कर रहा है ?

भारतीय जनता पार्टी ने इस बार विपक्षी दलों के सबसे बड़े मुस्लिम वोटबैंक पसमांदा समाज को साधने की रणनीति बनाई है। प्रदेश में मुस्लिमों की आबादी करीब पांच करोड़ है और यह मुस्लिम समाज प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 29 पर असर डालता है। प्रदेश में भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनावों के बाद से पसमांदा मुस्लिम और लाभार्थियों को साधने का अभियान चला रखा है।

मृत्युंजय दीक्षित

कुछ अन्य आपराधिक घटनाओं का संज्ञान लेना आवश्यक है क्योंकि इनसे पता चल रहा है कि प्रदेश के शहर-शहर में नफरत का जहर घोला जा रहा है। कुशीनगर, उन्नाव, बदांयू, जालौन और मुरादाबाद आदि जिलों में हुई घटनाएं और इन घटनाओं का पैटर्न बहुत ही चिंताजनक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए संकल्पवान हैं। वे स्वयं कानून व्यवस्था की छोटी से छोटी घटना पर पैनी दृष्टि रखते हैं और यही कारण है कि आज प्रदेश के जमनमानस में सुरक्षा का भाव जाग्रत हुआ है। प्रदेश की बेटियों में मनोबल ऊंचा हुआ है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट घोषणा कर रखी है कि यदि कोई शोहदा या अराजक तत्व किसी बहन-बेटी की सुरक्षा में सेंधमारी का प्रयास करेगा तो अगले चौराहे पर यमराज ही दिखलायी पड़ेंगे। मुख्यमंत्री की इस घोषणा का प्रभाव भी दिखाई पड़ रहा है। महिला सुरक्षा की चिंता करने के कारण भगवा धारी महंत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता मुस्लिम महिलाओं के बीच भी तेजी से बढ़ रही है जिसके कारण मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने वालों के मन में अशांति होना स्वाभाविक

है। सपा, बसपा, कांग्रेस व अन्य सभी छोटी पार्टियों के मन में यह भय है कि अगर 5 से 10 प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं व मतदाता का वोट अगर भाजपा को चला गया तो उनका तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा और भाजपा उप्र की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब हो जाएगी।

यही कारण है कि अब इन दलों ने भाजपा के खिलाफ जनमानस को भड़काने के लिए प्रदेश के वातावरण को अशांत करने के उपक्रम प्रारम्भ कर दिए हैं। हालात इतने अधिक बिगड़ गये हैं कि जब संसद के नये भवन का उदघाटन होने जा रहा था उस समय सपा के एक मुस्लिम सांसद ने बयान दिया कि नये संसद भवन में नमाज पढ़ने के लिए व्यवस्था की जाए। फिर संसद का सत्र समाप्त हो जाने के बाद भाजपा सांसद रमेश विधूड़ी और बसपा सांसद दानिश का प्रकरण प्रकट हो जाता है और सभी विरोधी दल आंख मूंदकर केवल और केवल दानिश के समर्थन में ही बयानबाजी करते हैं जबकि दानिश ने पहले प्रधानमंत्री को अपशब्द कहकर विधूड़ी को उकसाया था। सच तो ये है कि बसपा के मुस्लिम सांसद दानिश के पक्ष में सहानुभुति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ वातावरण बनाना चाहते हैं।

यहां पर कुछ अन्य आपराधिक घटनाओं का संज्ञान लेना आवश्यक है क्योंकि इनसे पता चल रहा है कि प्रदेश के शहर-शहर में नफरत का जहर घोला जा रहा है। कुशीनगर, उन्नाव, बदांयू, जालौन और मुरादाबाद आदि जिलों में हुई घटनाएं और इन घटनाओं का पैटर्न बहुत ही चिंताजनक है। उन्नाव में बाबा बोधेश्वर महादेव में सुबह पूजा कर रहे भक्तों पर एक मुस्लिम युवक जावेद ने अचानक डंडे से हमला कर दिया। हमले में सेवा निवृत्त कानूनगो सामेत तीन भक्त गंभीर रूप से घायल हो गये जबकि नौ अन्य लोगों को भी चोटें आईं जिन्हें इलाज के बाद छुट्टी मिल गयी। आरोपी जावेद को वहां उपस्थित भीड़ की सहायता से पुलिस ने पकड़ लिया और कोर्ट में प्रस्तुत करने के बाद जेल भेज दिया है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव होना स्वाभाविक था किंतु पुलिस व जनता की सतर्कता के कारण स्थिति संभल गई। सदा की तरह एक पक्ष के लोग जावेद को मानसिक रोगी बता रहे हैं किंतु जिस प्रकार से घटना को अंजाम दिया गया है उससे स्पष्ट है कि इस घटना व युवक के पीछे कोई न कोई षड्यंत्र तो अवश्य है, बिना किसी संरक्षण के यह अकेला युवक इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने में कैसे सफल हो गया यह जांच का भी विषय है और पुलिस प्रशासन इसमें जुटा है।

बदायूं में जुलूस ए मोहम्मदी के दौरान शेखूपुर गांव का वातावरण खराब करने का प्रयास किया गया। मुस्लिम युवकों ने शिव मंदिर के पास पहुंचते ही "सिर तन से जुदा" नारे लगाने प्रारम्भ कर दिये। जुलूस निकल जाने के बाद पुलिस ने कार्यवाही प्रारम्भ की और दो मुस्लिम युवकों शालू व ताजदार सहित 15 अन्य के विरुद्ध सांप्रदायिक वातावरण खराब करने व सामाजिक शत्रुता बढ़ाने की प्राथमिकी लिखी गई। इस घटना का वीडियो भी प्रसारित किया गया। जालौन और फतेहपुर में अराजक तत्वों ने तिरंगे में चक्र की जगह कुरान की आयतें लिखे झंडे को फहरा दिया। यह भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया जिसके आधार पर पुलिस ने तिरंगा बरामद कर वीडियो के आधार पर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है। फतेहपुर के बिंदकी में शहर काजी मोहम्मद रजा कादरी सहित 50 लोगों के खिलाफ राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करके चार संदिग्ध युवको में से तीन को हिरासत में लिया है। वहीं मुरादाबाद जिले में पिता-पुत्र ने अपने घर की छत पर पाकिस्तानी झंडा फहरा दिया और किसी ने उस घर के झंडे सहित वीडियो बनाकर पुलिस को दे दिया जिसके आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए घर पर जाकर झंडा उतारा और पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

निःसंदेह प्रदेश में यह सभी घटनाएं सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ही करवायी जा रही हैं और इसमें भी स्वार्थी राजनीति का तड़का लगा हुआ है। वहीं प्रदेश में लाख प्रयासों के बावजूद भी धर्मांतरण और लव जिहाद जैसी घटनाएं नहीं रुक पा रही हैं। श्री रामजन्मभूमि मंदिर के उद्घाटन की तिथि जैसे जैसे निकट आती जायगी वैसे वैसे ईर्ष्या व स्वार्थ की राजनीति से भरे हुए लोग इस प्रकार की घटनाओं को और तीव्रता व विकृति के साथ अंजाम दे सकते हैं। यह समय शासन प्रशासन के साथ साथ सर्व समाज के लिए भी सतर्कता का समय है क्योंकि आगामी दिनों में विजयादशमी और दीपावली जैसे प्रमुख हिंदू पर्व आ रहे हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि भी एक एक दिन करके निकट आ रही है, इस अवसर पर वृहद् हिन्दू समाज वातावरण को राममय बनाने का उत्सव भी करेगा। आगामी दिनों में पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के कारण राजनैतिक गतिविधियां भी उफान पर होंगी, जिनका लाभ भी अराजक तत्व उठाना चाहेंगे।

इतना सब कुछ होने के बाद भी केंद्र व प्रदेश सरकार की अनेक योजनाओं का सर्वाधिक लाभ गरीब मुस्लिम परिवारों को मिल रहा है। तीन तलाक जैसे कानूनों के कारण मुस्लिम समाज की महिलएं अपने आपको सुरक्षित महसूस कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी इन विषयों को लेकर मुस्लिम समाज विशेषकर मुस्लिम महिलाओं में अपनी पकड़ मजबूत बनाने का प्रयास कर रही है। कोई तार्किक कार्यक्रम पास में न होने के कारण विरोधी इसका उत्तर, प्रदेश में साम्प्रदायिक वारदातों को हवा देकर मुस्लिम तुष्टिकरण करके देना चाहते हैं और यही कारण है कि विरोधी दलों की शह पर प्रदेश में निरंतर अराजकता का वातावरण बनाने का असफल प्रयास किया जा रहा है।

भारतीय जनता पार्टी ने इस बार विपक्षी दलों के सबसे बड़े मुस्लिम वोटबैंक पसमांदा समाज को साधने की रणनीति बनाई है। प्रदेश में मुस्लिमों की आबादी करीब पांच करोड़ है और यह मुस्लिम समाज प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 29 पर असर डालता है। प्रदेश में भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनावों के बाद से पसमांदा मुस्लिम और लाभार्थियों को साधने का अभियान चला रखा है। विगत निकाय चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी ने कई सीटों पर पसमांदा मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा था और उनमें से अधिकांश सीटों पर सफलता भी मिली है। ■

भाजपा को दोबारा सत्ता में लाने के लिए

उत्तर प्रदेश पर खास ध्यान दे रहा आरएसएस

लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में बिसात बिछने लगी है। एक तरफ सियासी गठबंधन मजबूत किया जा रहा है तो दूसरी ओर अपने-अपने वोट बैंक को संगठित करने के लिए तमाम सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। एक तरफ महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण के लिए कानून बना दिया गया है। इस बिल के जरिए लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित हो जाएंगी।

अजय कुमार

गौरतलब है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष समारोह 2025 में होना है। इससे पहले आरएसएस हर गांव तक अपनी पैठ बना लेना चाहता है। लखनऊ में चल रहे कार्यक्रम के दौरान इस पर विशेष विमर्श चल रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में बिसात बिछने लगी है। एक

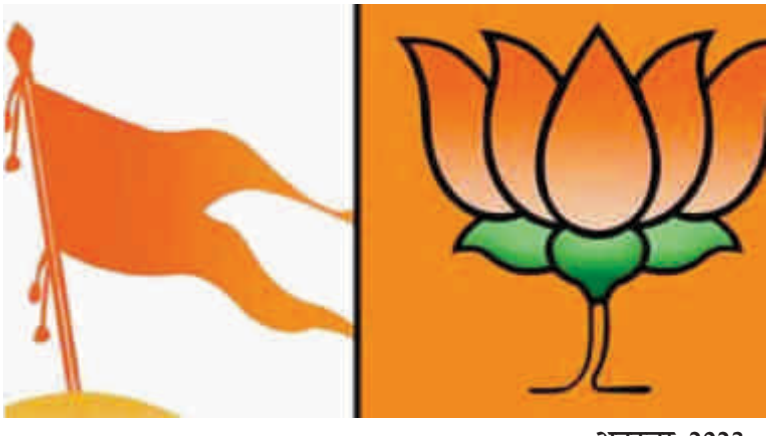

तरफ सियासी गठबंधन मजबूत किया जा रहा है तो दूसरी ओर अपने-अपने वोट बैंक को संगठित करने के लिए तमाम सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। एक तरफ महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण के लिए कानून बना दिया गया है। इस बिल के जरिए लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित हो जाएंगी। बीजेपी इसके जरिए देश की आधी आबादी के वोट अपनी झोली में डालना चाहती है तो अयोध्या में प्रभु रामलला का मंदिर भी अगले वर्ष जनवरी में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके जरिए बीजेपी हिन्दुत्व का कार्ड खेलना चाहती है। इससे इत्तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बैकडोर से बीजेपी को मजबूत करने की कोशिश में जुटा गया है। संघ की कोशिश हर गांव तक अपनी शाखा का विस्तार करना है। यह और बात है कि संघ अपनी तेजी को चुनाव से जोड़ने की बात से इंकार करते हुए कहता है कि वह तो अपने शताब्दी वर्ष समारोह की तैयारी कर रहा है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष समारोह 2025 में होना है। इससे पहले आरएसएस हर गांव तक अपनी पैठ बना लेना चाहता है। लखनऊ में चल रहे कार्यक्रम के दौरान इस पर विशेष विमर्श चल रहा है। रणनीति के तहत आरएसएस अपना विस्तार हर गांव तक करने की योजना पर काम कर रहा है। संघ राम मंदिर के उद्घाटन समारोह से लेकर अन्य योजनाओं को अपने तरीके से उठाने की तैयारी कर रहा है। अवध प्रांत में मोहन भागवत के चार दिवसीय दौरे को लोकसभा चुनाव के नजरिए से अहम माना जा रहा है। संगठन अपनी तैयारियों को यहां से धार देना शुरू करेगा। इस बार संघ की नजर मुस्लिम वोटरों पर भी है कि कैसे उन्हें अपने पाले में लाया जा सके, इसके लिए संघ प्रमुख

मोहन भागवत काफी दिनों को काम भी कर रहे हैं। वह मुस्लिम नेताओं और धर्मगुरुओं से न केवल मिलते हैं, बल्कि उनके कार्यकर्मो में भी जाते हैं। खैर, आरएसएस की ओर से राम मंदिर के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाए जाने की तैयारी की जा रही है। अगले साल जनवरी में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बन रहे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। संघ की ओर से रणनीति तैयार की गई है कि राम मंदिर के सपने को साकार करने वाली भावनाओं के ज्वार को पूरे देश में पैदा किया जाए। संघ की कोशिश इसके जरिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की धार को पैना करने की है। इसका असर लोकसभा चुनाव 2024 में दिख सकता है। भाजपा के पक्ष में अनुकूल वातावरण के निर्माण के लिए इसे अहम माना जा रहा है। सर संघ चालक मोहन भागवत की मुहिम को आगे बढ़ाने में हिन्दुत्व का एक बड़ा चेहरा रहे योगी आदित्यनाथ का भी सहयोग लिया जा रहा है। यह और बात है कि अब योगी अपने को यूपी के 24 करोड़ की जनता का संरक्षक बताते हुए सबके भले की बात करते हैं। भागवत और योगी की गत दिवस लखनऊ में मुलाकात हुई। करीब 45 मिनट की मुलाकात में सीएम योगी ने संघ प्रमुख को सरकार के कामकाज और उपलब्धियों की जानकारी दी। योजनाओं और उसके प्रभाव के बारे में बताया। सीएम ने सरसंघचालक को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे मंदिर की अपडेट जानकारी दी कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा अगले वर्ष जनवरी में मकर संक्रांति के बाद होनी तय है। इस कार्यक्रम को देशभर में मनाने और राष्ट्रवाद एवं सामाजिक समरसता को धार देने की रणनीति बनाई गई है। राम मंदिर निर्माण को देखते हुए अयोध्या को नए और भव्य तरीके से विकसित करने की योजना पर चल रहे काम के बारे में भी संघ प्रमुख को बताया गया।

संघ प्रमुख मोहन भागवत का कार्यक्रम शनिवार को बैठकों के साथ शुरू हुआ। अवध प्रांत में संघ के सांगठनिक विस्तार और सेवा प्रकल्पों को लेकर बैठक के द्वारा अवध प्रांत में संघ के कामकाज की समीक्षा के साथ आगे की कार्ययोजना तैयार की जा रही है। वर्ष 2025 में संघ के शताब्दी समारोह को देखते हुए आरएसएस सभी गांवों तक अपनी पहुंच बढ़ाने की योजना पर काम कर रहा है। ■

चुनावी रथ में ही क्यों सवार होती हैं

जन-हित योजनाएं

लोकतन्त्र में यह दायित्व सरकारों का ही होता है कि वे आम आदमी के जीवन की आवश्यक जरूरतों की पूर्ति करने की व्यवस्था हेतु अनिवार्य आधारभूत ढांचा खड़ा करें। निश्चित ही एक सराहनीय शुरूआत गहलोत ने की है वह देश की सभी राज्य सरकारों के लिए नजीर बन सकती है।

ललित गर्ग

निश्चित ही राजस्थान में लोकलुभावनी योजनाओं का जनता को लाभ मिला है, राजस्थान का कायाकल्प भी हुआ। गहलोत अपने राजनीतिक जीवन की सबसे चुनौतीपूर्ण पारी खेलते हुए एक कद्दावर नेता के रूप में सामने आ रहे हैं। लेकिन मतदाता के मन में ये योजनाएं हैं या और कुछ? यह वक्त ही बतायेगा।

आजादी के अमृतकाल के पहले लोकसभा एवं पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव की आहट अब साफ-साफ सुनाई दे रही है, राज्यों में चुनावी सरगर्मियां उग्र हो चुकी है। भारत के सभी राजनीतिक दल अब पूरी तरह चुनावी मुद्रा में आ गये हैं और प्रत्येक प्रमुख राजनैतिक दल इसी के अनुरूप बिछ रही चुनावी बिसात में अपनी गोटियां सजाने में लगे दिखाई पड़ने लगे हैं। जिन पांच राज्यों में चुनाव होने हैं, उनमें राजस्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहुत पहले ही विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है, वे हर दिन किसी-न-किसी लुभावनी एवं जनकल्याणकारी योजना की घोषणा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा सहित विभिन्न योजनाओं की तरह अब उन्होंने प्रदेश के 240 राजकीय विद्यालयों को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में रूपांतरित करने का ऐलान किया किया है। निश्चित ही एक आदर्श राज्य के रूप में गहलोत की योजनाओं की देशभर में चर्चा हो रही है, लेकिन क्या इन योजनाओं के बल पर वे पुनः सत्ता प्राप्त करने में सफल हो पायेंगे? असल में गहलोत का मुकाबला इस बार सीधे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से होने जा रहा है। मोदी पहले सीकर एवं अब जोधपुर में जनता का मानस बदलने एवं राजस्थान के गहलोत सरकार के घोटालों को उजागर किया है।

लोकलुभावन घोषणा एवं मुक्त की रेवड़ियां राजस्थान की तरह ही मध्यप्रदेश में शिवराजसिंह चौहान भी बांट रहे हैं, अभी तो इनके बल पर चुनाव जीते जा सकते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए दोनों ही प्रांतों की चुनी सरकारों को एड़ी-चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि राज्य की वित्तीय स्थिति उन्हें पूरा करने की अनुमति दे पाएंगी, इसमें संदेह है। जैसी गारंटियां, लोकलुभावन वादे एवं मुक्त की रेवड़ियां देने की परम्परा दक्षिण से शुरु हुई थी, वैसी ही अब देश के अन्य प्रांतों में वहां की सरकारें कर रही हैं। अभी हाल में दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने दस गारंटियां दी थीं। ये गारंटियां और कुछ नहीं लोकलुभावन वादे ही थे, जिन्हें जनकल्याण का नाम दिया गया है। मध्य प्रदेश में मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह चौहान एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव से छह महीने पहले ही लोक कल्याणकारी योजनाओं की झड़ी लगा रखी है जिससे राज्य का चुनावी माहौल और गर्मा रहा है।

निश्चित ही राजस्थान में लोकलुभावनी योजनाओं का जनता को लाभ मिला

है, राजस्थान का कायाकल्प भी हुआ। गहलोत अपने राजनीतिक जीवन की सबसे चुनौतीपूर्ण पारी खेलते हुए एक कद्दावर नेता के रूप में सामने आ रहे हैं। लेकिन मतदाता के मन में ये योजनाएं हैं या और कुछ? यह वक्त ही बतायेगा। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि मतदाता अब ज्यादा जागरूक हुआ है तो गहलोत भी ज्यादा सर्तक, समझदार एवं चालाक हुए हैं। उन्होंने जिस प्रकार चुनावी शतरंज पर काले-सफेद मोहरें बिछाने शुरु कर दिये हैं, उससे मतदाता भी उलझा हुआ प्रतीत करेगा। अपने हित की पात्रता नहीं मिल रही है। कौन ले जाएगा प्रदेश की लगभग आठ करोड़ जनता को आजादी के अमृतकाल में। सभी नंगे खड़े हैं, मतदाता किसको कपड़े पहनाएगा, यह एक दिन के राजा पर निर्भर करता है। सभी इस एक दिन के राजा को लुभाने में जुटे हैं। कोई मुफ्तखोरी की राजनीति का सहारा लेकर चुनाव जीतने की कोशिश करने में जुटा है तो कोई गठबंधन को आधार बनाकर चुनाव जीतने के सपने देख रहा है।

विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां उग्रता पर है, इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प एवं चुनौतीपूर्ण होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं गृहमंत्री अमित शाह भाजपा की स्थिति को मजबूती देते हुए गहलोत सरकार को पछताड़े में लगे हैं। लेकिन भाजपा की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह अपनी हार के कारणों को बड़ी गहराई से लेते हुए उन कारणों को समझने एवं हार को जीत में बदलने के गणित को बिठाने में माहिर है। गहलोत प्रखर नेता के रूप में न केवल भीतर संघर्ष कर रहे हैं बल्कि भाजपा को चुनौती देने का हरसंभव प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने दूरगामी सोच एवं राजनीतिक कौशल से अनेक प्रभावी योजनाओं को लागू किया है। आज राजस्थान एक 'आदर्श राज्य' के रूप में उभरा है या नहीं? यह देश के सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में से एक है भी या नहीं है? यह विश्लेषण के विषय हैं। आज देश में राजस्थान की चर्चा सबसे अच्छी सड़कों, सबसे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं, सबसे अधिक विश्वविद्यालयों व सबसे आगे बढ़ने वाले राज्य से अधिक गहलोत की योजनाओं के रूप में हो रही है और यह सब योजनाएं चुनावी रथ पर सवाल होकर जीत को सुनिश्चित करने की चेष्ठा है।

किसी भी राष्ट्र के जीवन में चुनाव सबसे महत्त्वपूर्ण घटना होती है। यह एक यज्ञ होता है। लोकतंत्र प्रणाली का सबसे मजबूत पैर होता है। राष्ट्र के प्रत्येक वयस्क के संविधान प्रदत्त पवित्र मताधिकार प्रयोग का एक दिन। सत्ता के सिंहासन पर अब कोई राजपुरोहित या राजगुरु नहीं बैठता अपितु जनता अपने हाथों से तिलक लगाकर नायक चुनती है। लेकिन पांच राज्यों में जनता तिलक किसको लगाये, इसके लिये सब तरह के साम-दाम-दंड अपनाये जा रहे हैं। हर राजनीतिक दल अपने लोकलुभावन वायदों एवं घोषणाओं को ही गीता का सार व नीम की पत्ती बता रहे हैं, जो सब समस्याएं मिटा देगी तथा सब रोगों की दवा है। लेकिन ऐसा होता तो आजादी के अमृतकाल तक पहुंच जाने के बाद भी देश एवं प्रदेश गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अफसरशाही, बेरोजगारी, अशिक्षा, स्वास्थ्य समस्याओं से नहीं जुझता दिखाई देता। ऐसी स्थिति में मतदाता अगर बिना

विवेक के आंख मूंदकर मत देगा तो परिणाम उस उक्ति को चरितार्थ करेगा कि "अगर अंधा अंधे को नेतृत्व देगा तो दोनों खाई में गिरेंगे।"

राजस्थान के चुनाव का नतीजा अभी लोगों के दिमागों में है। मतपेटियां क्या राज खोलेंगी, यह समय के गर्भ में है। पर एक संदेश इस चुनाव से मिलेगा कि अधिकार प्राप्त एक ही व्यक्ति अगर ठान ले तो अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार, महंगाई, गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य आदि समस्याओं पर नकेल डाली जा सकती है। लेकिन देश एवं प्रदेश बनाने एवं विकास की ओर अग्रसर करने की बजाय सभी दल मुक्त रेवडियां बांट कर एक अकर्मण्य पीढ़ी को गढ़ने की कुचेष्टा करते हैं या येन-केन-प्रकारेण चुनाव जीत का सेहरा अपने सीर पर बांधना चाहते हैं। कई बार तो ऐसी घोषणाएं भी कर दी जाती हैं, जिन्हें पूरा करना संभव नहीं होता। उन्हें या तो आधे-अधूरे ढंग से पूरा किया जाता है या देर से अथवा उनके लिए धन का प्रबंध जनता के पैसों से ही किया जाता है। उदाहरणस्वरूप दिल्ली एवं कर्नाटक सरकार ने बिजली मुफ्त देने के वादे को पूरा करने के लिए बिजली महंगी कर दी या नई गलियां निकाल ली। इसी तरह पंजाब सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ा दिया। चुनाव जीतने के लिए वित्तीय स्थिति की अनदेखी कर लोकलुभावन वादे करना अर्थव्यवस्था के साथ खुला खिलवाड़ है। इस पर रोक नहीं लगी तो इसके दुष्परिणाम जनता को ही भुगतने पड़ेंगे। जो चुनाव सशक्त एवं आदर्श शासक नायक के चयन का माध्यम होता है, उससे अगर नकारा, ठग एवं अलोकतांत्रिक नेताओं का चयन होता है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण एवं देश की विडम्बना है।

लेकिन गहलोत की ताजा शिक्षा योजना यदि चुनाव से न जुड़ी होती तो इस एक योजना से वे अनुकरणीय एवं आदर्श राजनेता बनकर उभरते? प्रश्न है कि ऐसी योजनाएं चुनाव के समय ही क्यों लागू की जाती है? आजादी के अमृतकाल में भी देश का गरीब तबका समुचित शिक्षा से वंचित है। विद्यालयों की फीस देने में वह खुद को असमर्थ पाता है जिसकी वजह से उसमें हताशा का संचार भी देखने भी आया है। ऐसे वातावरण में सरकारों का ही यह दायित्व बनता है कि वे समाज के निचले तबकों को ऊपर उठाने के लिए शिक्षा के स्तर से ही ऐसी शुरूआत करें जिससे गरीब से गरीब का मेधावी बालक भी अपने सपनों को पूरा करके ऊंचे से ऊंचे पद तक अपनी योग्यता के अनुसार पहुंच सके। लोकतन्त्र में यह दायित्व सरकारों का ही होता है कि वे आम आदमी के जीवन की आवश्यक जरूरतों की पूर्ति करने की व्यवस्था हेतु अनिवार्य आधारभूत ढांचा खड़ा करें। निश्चित ही एक सराहनीय शुरूआत गहलोत ने की है वह देश की सभी राज्य सरकारों के लिए नजीर बन सकती है। राजस्थान सरकार ने गांवों के स्तर पर अंग्रेजी माध्यम के आधुनिक स्कूल खोल कर यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि किसी किसान-मजदूर का बेटा-बेटी भी केवल अंग्रेजी ज्ञान न होने की वजह से ही जीवन में न पिछड़े और उच्च शिक्षा के मोर्चे पर भी आगे रहे। ■

देश की अर्थव्यवस्था का ढांचा मजबूत करने और विश्व की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में स्थान बनाने के लिए देश में महंगाई, बेरोजगारी, घरेलू बचत, आर्थिक असमानता को कम करने की दिशा में प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाना चाहिए। एक ऐसा परिवेश तैयार करने की आवश्यकता है, जिसमें बेहतर जीवन-निर्वाह, स्वास्थ्य और शिक्षा, यथोचित रोजगार, न्याय और उन्नत व उत्कृष्ट तकनीक तक देश के सभी लोगों की पहुंच बनाई जा सके।

गिरती घरेलू बचत एवं बढ़ती

महंगाई से त्रस्त अर्थव्यवस्था

रमेश राव

आगामी लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के मध्यनजर महंगाई का लगातार बढ़ते रहना चिंता का विषय है। घरेलू बचत, महंगाई, बढ़ता व्यक्तिगत कर्ज, बढ़ते व्यक्तिगत खर्चे आदि को लेकर निम्न एवं मध्यम वर्ग परेशान है। इस परेशानी के समाधान की बजाय सत्ता एवं विपक्ष दल एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी ताजा मासिक बुलेटिन में माना है कि खाद्य मुद्रास्फीति को काबू करना कठिन साबित हो रहा है। आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत की घरेलू बचत दर वित्त वर्ष 2022-23 में पांच दशकों के निचले स्तर पर पहुंच गई। 18 सितंबर को जारी इन आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में देश की शुद्ध घरेलू बचत पिछले साल की तुलना में 19 फीसदी कम रही है। 2021-22 में देश की शुद्ध घरेलू बचत जीडीपी के 7.2 फीसदी पर थी जो इस साल और घटकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लगभग 5 दशक के निचले स्तर 5.1 प्रतिशत पर आ गई है। अनेक मोर्चों पर भारत की तस्वीर आशा का संचार कर रही है, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर चिन्ता का सबब लगातार बना हुआ है, हालांकि समूची दुनिया में आर्थिक असंतुलन बना हुआ है, भारत ने फिर भी खुद को काफी संभाले हुए हैं। किसी देश की अर्थव्यवस्था इस पैमाने पर भी आंकी जाती है कि उसकी घरेलू बचत, प्रति व्यक्ति आय और क्रयशक्ति की स्थिति क्या है। भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष में परिवारों की शुद्ध वित्तीय बचत में करीब पचपन फीसद की गिरावट आई और यह सकल घरेलू उत्पाद के 5.1 फीसद पर पहुंच गई। वित्त मंत्रालय ने घरेलू बचत में गिरावट पर सफाई देते हुए कहा है कि लोग अब आवास और वाहन जैसी भौतिक संपत्तियों में अधिक निवेश कर रहे है। इसका असर घरेलू बचत पर पड़ा है। मंत्रालय ने भरोसा दिलाया है कि संकट जैसी कोई बात नहीं है। सरकार ने यह भी कहा है कि पिछले दो साल में परिवारों को दिए गए खुदरा ऋण का 55 फीसद आवास, शिक्षा और वाहन पर खर्च किया गया है। परिवारों के स्तर पर वित्त वर्ष 2020-21 में 22.8 लाख करोड़ की शुद्ध संपत्ति जोड़ी गई थी। 2021-22 में लगभग सत्रह लाख

करोड़ और वित्तवर्ष 2022-23 में 13.8 लाख करोड़ रुपये की वित्तीय संपत्तियां बढ़ी हैं। इसका मतलब है कि लोगों ने एक साल पहले और उससे पहले के साल की तुलना में इस साल कम वित्तीय संपत्तियां जोड़ी हैं। सरकार के अनुसार ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि वे अब कर्ज लेकर घर और वाहन जैसी भौतिक संपत्तियां खरीद रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले दो साल में आवास और वाहन ऋण में दोहरे अंक में वृद्धि हुई है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि महामारी के बाद से लोग काफी सचेत हुए हैं। वे जोखिम वाले निवेश से बच रहे हैं। दूसरी बात बचत खातों पर ब्याज पर दर बहुत आकर्षक नहीं हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित बी-20 बैठक में बोलते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा भी कि ब्याज दरें बढ़ाकर महंगाई नियंत्रित करने की कीमत आर्थिक विकास को चुकानी भारी पड़ सकती है। सरकार चाहे जो तर्क दे पर घरेलू बचत गिरना कोई शुभ संकेत नहीं कहा जा सकता। घरेलू बचत सामान्य सरकारी वित्त और गैर-वित्तीय कंपनियों के लिए कोष जुटाने का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रभावी जरिया होती है। देश की कुल बचत में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखने वाली बचत का लगातार गिरना निम्न और मध्यमवर्ग ही नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था के लिए चिंता की बात है।

लगातार महंगाई का बढ़ना भी न केवल आमजन के लिये बल्कि सरकार के लिये चिन्ता का कारण है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के अनुमानों से पता चलता है कि जुलाई (7.4 प्रतिशत) की तुलना में अगस्त में यह घटकर 6.8 फीसदी हो गई है। यहां तक कि खाद्य वस्तुओं की महंगाई भी जुलाई के उच्चतम स्तर पर 11.5 फीसदी से घटकर अगस्त में 9.94 प्रतिशत हो गई। इन संकेतों से भले ही राहत की सांसें मिली हो, बावजूद इसके यह अब भी ज्यादा है। यह गिरावट मुख्यतः सब्जियों की कीमतों में कमी के कारण आई है, जो जुलाई की 37.4 फीसदी की तुलना में अगस्त में 26.1 प्रतिशत थी। हालांकि अनाज और दालों में महंगाई दोहरे अंकों में बनी हुई है, जिनमें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के मद्देनजर गिरावट की संभावना फिलहाल नहीं दिख रही। आरबीआई ने स्वीकारा है कि खाद्य मुद्रास्फीति को काबू करना कठिन साबित हो रहा है। मगर अधिकारियों को महंगाई कम करने का महत्वपूर्ण काम सौंपा गया है। स्पष्ट है कि दबाव और प्रतिबंधों के माध्यम से महंगाई को काबू में करने के प्रयास काफी हद तक नाकाम रहे हैं। घरेलू आपूर्ति में कमी के कारण कई खाद्य वस्तुओं, विशेषकर अनाज व दालों में महंगाई रूकने का नाम नहीं ले रही है। गेहूं का उत्पादन गरमी और बेमौसम बारिश के कारण प्रभावित है। यही कारण है कि मई 2022 में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। चावल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दालों का भी यही हाल है। महंगाई अक्सर सत्तापक्ष के लिये राजनीतिक चुनौती बनती रही है, चुनावों में हार-जीत को बहुत गहराई से प्रभावित करने में महंगाई आधार बनती रही है। महंगाई कम करने के लिए हमें वैकल्पिक रास्ते तलाशने होंगे, जो आर्थिक विकास या किसानों के हितों को प्रभावित किए बिना उपभोक्ताओं की रक्षा करें। विकृत एवं असंतुलित बाजार व्यवस्था ने भी अनेक आर्थिक विसंगतियों को जन्म दिया है। एक आदर्श व्यवस्था का चिन्तन ही वर्तमान की आर्थिक समस्याओं का समाधान हो सकता है। वर्तमान सरकार ने गरीबी दूर करने में सफलता पाई है, लेकिन उसकी सोच अमीरी बढ़ाने की भी रही है। छोटे उद्योग, सबके पास अपना काम, हर व्यक्ति के लिये रोजगार की सुनिश्चितता, कोई भी इतना बड़ा न हो कि जब चाहे अपने से निर्बल को दबा सके। एक आदमी के शक्तिशाली होने का मतलब है, कमजोरों पर निरन्तर मंडराता खतरा। एक संतुलन बने। सबसे बड़ी बात है मानवीय अस्तित्व और मानवीय स्वतंत्रता की। इस पर आंच न आये और आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाये, ऐसी अर्थव्यवस्था की आज परिकल्पना आवश्यक है। तभी बढ़ती महंगाई, आय असंतुलन एवं घटती बचत पर काबू पाया जा सकता है। आय असमानता, महंगाई, बेरोजगारी एक कल्याणकारी राज्य की सबसे बड़ी विडंबना है। यह जब गंभीर रूप से उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है तो उदार आर्थिक सुधारों के लिए सार्वजनिक समर्थन कम हो जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत में नव उदारवादी नीतियों से आर्थिक वृद्धि दर को जरूर पंख लगे हैं, लेकिन इससे अमीरों की जितनी अमीरी बढ़ी है, उस दर से गरीबों की गरीबी दूर नहीं हुई है। परिणामस्वरूप आर्थिक असमानता की खाई साल दर साल चौड़ी होती जा रही है। इसलिए हमारे नीति निर्माताओं तथा योजनाकारों को इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि सर्व समावेशी विकास के लक्ष्य को कैसे हासिल करें? ताकि हाशिये पर छूटे हुए वंचितों, पिछड़ों तथा शोषितों को विकास की मुख्यधारा में लाया जा सके। वर्तमान में आर्थिक असमानता से उबरने का सबसे बेहतर उपाय यही होगा कि वंचित वर्ग को अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार उपलब्ध कराते हुए सुदूरवर्ती गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाए। इसके लिए सरकार को अपनी कल्याणकारी योजनाओं पर कहीं ज्यादा खर्च करना होगा। स्वास्थ्य और शिक्षा पर कहीं ज्यादा राशि आवंटित करनी होगी। अभी इन मदों पर हमारा देश बहुत ही कम खर्च करता है। भारत में वह क्षमता है कि वह नागरिकों को एक अधिकारयुक्त जीवन देने के साथ ही समाज में व्याप्त असमानता को दूर कर सकता है। सच्चाई यह भी है कि कोई भी देश तेज आर्थिक विकास के बिना बड़े पैमाने पर गरीबी के खिलाफ जंग जीतने में कामयाब नहीं रहा है। अतः आर्थिक सुधारों की रूपरेखा कुछ ऐसे तय करनी होगी, जिससे कि महंगाई, घटती बचत, आय असमानता को कम किया जा सके तथा देश में ऐसा नया आर्थिक माहौल विकसित किया जा सके, जो रोजगार, आम आदमी और गरीबों की खुशहाली पर केंद्रित हो। देश की अर्थव्यवस्था का ढांचा मजबूत करने और विश्व की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में स्थान बनाने के लिए देश में महंगाई, बेरोजगारी, घरेलू बचत, आर्थिक असमानता को कम करने की दिशा में प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाना चाहिए। एक ऐसा परिवेश तैयार करने की आवश्यकता है, जिसमें बेहतर जीवन-निर्वाह, स्वास्थ्य और शिक्षा, यथोचित रोजगार, न्याय और उन्नत व उत्कृष्ट तकनीक तक देश के सभी लोगों की पहुंच बनाई जा सके। ■

महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

हिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा वर्ष 1996 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल से ही की जाती रही है। परन्तु तत्कालीन सरकार के पास बहुमत नहीं होने के कारण इस विधेयक को स्वीकृति नहीं मिल सकी। चूंकि इस बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ है। इसलिए यह विधेयक आसानी से पारित हो गया। इस विधेयक के पारित होने से इसके राजनीतिकरण पर भीविराम लग गया। नि:संदेह इस वेधेयक के लागू होने से राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी।

-डॉ. प्रियंका नितिन वर्मा

भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समय-समय पर दोहराया है कि उनकी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हर संभव प्रयास करेगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसी प्रयास का परिणाम है। हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने महिला आरक्षण विधेयक 2023 अथवा नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर दिया। यह विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विगत 21 सितंबर, 2023 को राज्यसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में कहा कि दो दिन से अत्यंत महत्वपूर्ण इस विधेयक पर विस्तार से चर्चा हो रही है। करीब 132 माननीय सदस्यों ने दोनों सदन में मिलाकर के बहुत ही सार्थक चर्चा की है और भविष्य में भी इस चर्चा के एक-एक शब्द आने वाली हमारी यात्रा में हम सबको काम आने वाला है और इसलिए हर बात का अपना एक महत्व है, मूल्य है। मैं सभी माननीय सांसदों ने अपनी बात के प्रारंभ में तो पहले ही कहा है कि हम इसका समर्थन करते हैं और इसके लिए मैं सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ये जो स्पिरिट पैदा हुई है, ये स्पिरिट देश के जन-जन में एक नया आत्मकविश्वामस पैदा करेगा और हम सभी माननीय सांसदों ने और सभी राजनीतिक दलों ने एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई है। नारी शक्ति को एक विशेष सम्मान, सिर्फ विधेयक पारित होने से मिल रहा है, ऐसा नहीं है। इस विधेयक के प्रति देश के सभी राजनीतिक दलों की सकारात्मक सोच होना, ये हमारे देश की नारी शक्ति को एक नई ऊर्जा देने वाली है। ये एक नए विश्वास के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देने में नेतृत्व के साथ आगे आएगी, ये अपने आप में भी हमारे उज्ज्वल भविष्य् की गारंटी बनने वाली है।

उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में मतदान करने वाले करने वाले सभी राज्यसभा सांसदों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह हमारे देश की लोकतांत्रिक यात्रा में एक निर्णायक क्षण है। उन्होंने देश के 140 करोड़ नागरिकों को बधाई दी। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह केवल एक कानून नहीं है, बल्कि उन अनगिनत महिलाओं का सम्मान है जिन्होंने हमारे देश को

बनाया है, और यह उनकी आवाज अधिक प्रभावी तरीके से सुना जाना सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता में एक ऐतिहासिक कदम है।

इससे पूर्व केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोक सभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा में भाग लिया। चर्चा में बोलते हुए उन श्री अमित शाह ने कहा था कि 19 सितम्बर 2023 का दिन भारतीय संसद के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि इस दिन गणेश चतुर्थी के अवसर पर नई संसद में पहली बार कामकाज हुआ और वर्षों से लंबित महिलाओं को आरक्षण का अधिकार देने वाला बिल सदन में पेश हुआ। उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने 140 करोड़ की आबादी में 50 प्रतिशत हिस्से वाली मातृशक्ति को सच्चे अर्थों में सम्मानित करने का काम किया है।

उन्होंने कहा कि कुछ दलों के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक ऐजेंडा हो सकता है लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार के लिए महिला सशक्तिकरण मान्यता का मुद्दा है। उन्होंने कहा कि 2014 में देश की महान जनता ने 30 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री का पदभार सम्भालने के दिन से ही महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सहभागिता श्री नरेन्द्र मोदी जी नेतृत्व में सरकार की श्वास और प्राण बने हुए हैं।

उन्होंने कहा कि महिलाएं, पुरुषों से भी अधिक सशक्त हैं और इस विधेयक से अब डिसिजन और पॉलिसी मेकिंग में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ये बिल समाज व्यवस्था की त्रुटि को सुधारने, महिलाओं की प्रतिभागिता बढ़ाने और उनका सम्मान करने के लिए लेकर आई है। उन्होंने कहा कि आज ये एक ऐसा मौका है जब इस सदन को पूरे विश्व को एक संदेश देने की जरूरत है कि मोदी जी की 'वुमन लीड डिवेलप्मन्ट' की कल्पना को पूरा करने के लिए पूरा सदन एकमत है।

उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक लाने के पहले की सरकारों द्वारा चार प्रयास हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक सबसे पहली बार 1996 में देवेगौड़ा सरकार लेकर आई, इसके बाद इसे सीमा मुखर्जी की अध्यक्षता वाली एक समिति को दे दिया गया और समिति ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी लेकिन फिर वो विधेयक कभी इस सदन तक नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 1998 में ये विधेयक लेकर आई, लेकिन विपक्ष ने इसे सदन में पेश ही नहीं करने दिया। उन्होंने कहा कि इसके बाद एक बार फिर अटल जी की सरकार बिल लेकर आई लेकिन एक बार फिर इस पर चर्चा नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि इसके बाद फिर डॉ. मनमोहन सिंह जी की सरकार संशोधन विधेयक राज्य सभा में लेकर आई, जहां पारित होने के बाद ये विधेयक लोक सभा में आ ही नहीं सका।

उन्होंने पक्ष-विपक्ष के सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि सब एकत्रित होकर इस नई शुरुआत के माध्यम से आज सर्वानुमति से संविधान को संशोधित कर मातृशक्ति को आरक्षण देने का काम करें। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रावधान के अनुसार संसद में चुनकर आने वाले सदस्यों की तीनों श्रेणियों – सामान्य (जिसमें ओबीसी शामिल हैं), अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति – में मोदी सरकार ने 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को दे दिया है। उन्होंने कहा कि इस संविधान संशोधन की धारा 330 (ए) और धारा 332 (ए) के माध्यम से महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही तीनों श्रेणियों में वर्टिकल आरक्षण देकर एक-तिहाई सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया को निर्धारित करने वाली एक महत्वपूर्ण इकाई का कानूनी प्रावधान है और वह नियुक्ति से होता है लेकिन क्वासी ज्यूडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं। उन्होंने कहा कि इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करते हैं और इसमें चुनाव आयुक्त के एक प्रतिनिधि भी होते हैं। उन्होंने कहा कि जिन एक-तिहाई सीटों को रिजर्व करना है, उन सीटों का चयन डिलिमिटेशन कमीशन करेगा। ये कमीशन हर राज्य में जाकर, ओपन हियरिंग देकर एक पारदर्शी पद्धति से इसके लिए नीति निर्धारण करता है। उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन लाने के पीछे एकमात्र उद्देश्य पारदर्शिता लाना है। उन्होंने कहा कि इस कमीशन के गठन से किसी प्रकार की देरी नहीं होगी, चुनाव के बाद जनगणना और डिलिमिटेशन दोनों होंगे और जल्द ही वह दिन आएगा जब इस सदन में एक-तिहाई महिला सांसद बैठकर देश के भाग्य को तय करेंगी। उल्लेखनीय है कि महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा वर्ष 1996 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल से ही की जाती रही है। परन्तु तत्कालीन सरकार के पास बहुमत नहीं होने के कारण इस विधेयक को स्वीकृति नहीं मिल सकी। चूंकि इस बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ है। इसलिए यह विधेयक आसानी से पारित हो गया। इस विधेयक के पारित होने से इसके राजनीतिकरण पर भीविराम लग गया। नि:संदेह इस वेधेयक के लागू होने से राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। ■

कौन-से मुद्दे चुनावों में ह

राज्य में 1993 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद का इतिहास कहता है कि उसके बाद हर विधानसभा चुनाव में एक बार कांग्रेस तो एक बार भाजपा को सत्ता की बागडोर मिलती रही है। यानी कोई भी पार्टी लगातार दो बार सरकार नहीं बना पाई। इस 'परिपाटी' के लिहाज से इस बार सत्ता में आने की 'बारी' भाजपा की है। यह समीकरण उस समय बन रहा है जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेता राज्य में 'डबल इंजिन की सरकार' बनाने की अपील कर रहे हैं ताकि केंद्र व राज्य में एक ही पार्टी की सरकार हो और विकास को गति दी जा सके। वहीं कांग्रेस नेताओं का दावा है कि इस बार राज्य का 'रिवाज' टूटेगा। यानी एक बार फिर कांग्रेस की सरकार आएगी।

...ावी रहेंगे

नीरज कुमार दुबे

चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद सभी दलों के नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं लेकिन देखना होगा कि जनता के मन में क्या है। आइये राज्यवार राजनीतिक हालात, मुद्दों और विभिन्न पार्टियों के समक्ष उपलब्ध अवसरों और चुनौतियों पर एक नजर डालते हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले होने वाले पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव कार्यक्रम के ऐलान के साथ ही अब सबकी निगाह इस बात पर लग गयी है कि सत्ता का सेमीफाइनल कौन जीतेगा? सवाल यह भी है कि क्या जो सेमीफाइनल जीतेगा वही लोकसभा चुनाव भी जीतेगा? हम आपको बता दें कि जिन पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ है उसमें कांग्रेस के पास दो राज्यों- छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकार है तो वहीं भाजपा के पास मध्य प्रदेश में सरकार है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनावों के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार बनी थी लेकिन आंतरिक मतभेदों के चलते कमल नाथ की सरकार गिर गयी थी और कांग्रेस विधायकों के दल बदल के चलते शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर मुख्यमंत्री बन गये थे। इसके अलावा तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति की सरकार है तो वहीं मिजोरम में क्षेत्रीय दल मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता में है।

बहरहाल, चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद सभी दलों के नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं लेकिन देखना होगा कि जनता के मन में क्या है। आइये राज्यवार राजनीतिक हालात, मुद्दों और विभिन्न पार्टियों के समक्ष उपलब्ध अवसरों और चुनौतियों पर एक नजर डालते हैं-

छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में 2003 से 2018 के बीच 15 वर्षों तक शासन करने वाली भाजपा के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर के कारण कांग्रेस ने 2018 विधानसभा चुनाव में भारी जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के पास वर्तमान में 90 सदस्यीय राज्य विधानसभा में 71 सीटें हैं। पार्टी ने आगामी चुनावों में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार की किसान समर्थक, आदिवासी समर्थक और गरीब समर्थक योजनाओं के दम पर 75 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। सत्ताधारी दल मुख्यमंत्री बघेल की लोकप्रियता को भुनाने की कोशिश में है क्योंकि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और ग्रामीण मतदाताओं पर उनकी अच्छी खासी पकड़ है।

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ताकत के बारे में बात करें तो देखने को मिलता है कि राजीव गांधी किसान न्याय और गोधन न्याय योजना सहित कई कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन, किसानों और ग्रामीण आबादी के लिए योजनाएं, बेरोजगारी भत्ता के अलावा समर्थन मूल्य पर बाजरा तथा विभिन्न वन उपज की खरीद कांग्रेस के पक्ष में मतदाताओं को आकर्षित कर सकती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्थानीय लोगों में अपनी लोकप्रियता बढ़ाते हुए अपनी छवि 'माटी पुत्र' के रूप में विकसित की है। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और ग्रामीण मतदाताओं पर उनकी अच्छी खासी पकड़ है। इसके अलावा, पिछले पांच वर्षों में पार्टी ने बूथ स्तर तक अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत किया है। राजीव युवा मितान क्लब योजना से जुड़े करीब तीन लाख युवा, मतदाताओं को अपने पक्ष में गोलबंद करने में पार्टी की मदद कर सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य राज्य के युवाओं को रचनात्मक कार्यों से जोड़ना, नेतृत्व कौशल विकसित करना और उन्हें उनकी सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक करना है। कांग्रेस ने 2018 के बाद छत्तीसगढ़ में पांच विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भी जीत हासिल की थी और राज्य में अपनी मजबूत स्थिति का अहसास कराया था।

इसके अलावा, कांग्रेस की कमजोरियों की बात करें तो आपको बता दें कि पार्टी की राज्य इकाई में गुटबाजी और अंदरुनी कलह है। पिछले पांच वर्षों में, पार्टी में मुख्यमंत्री बघेल के धुर विरोधी टी.एस. सिंहदेव ने कई बार विद्रोह का झंडा उठाया है। आखिरकार पार्टी को इस साल की शुरुआत में उन्हें उपमुख्यमंत्री नियुक्त करके संतुष्ट करना पड़ा। वहीं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के भी बघेल के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। हालांकि, कुछ महीने पहले ही उन्हें राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इन सबके बावजूद पार्टी में अंदरूनी कलह अभी भी बरकरार बताई जाती है। भूपेश बघेल सरकार राज्य में कोयला परिवहन, शराब बिक्री, जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) कोष के उपयोग और लोक सेवा आयोग भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रही है। वर्तमान शासन के दौरान राज्य में धर्मांतरण, सांप्रदायिक हिंसा और झड़पों की कुछ घटनाएं हुईं, जिससे विपक्षी दल भाजपा को कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाने का मौका मिला।

कांग्रेस के पास अवसरों की बात करें तो आपको बता दें कि पिछले लगभग पांच वर्षों में भाजपा कांग्रेस पर प्रभावी हमला करने में विफल रही है। भाजपा में नेतृत्व का मुद्दा लगातार बना हुआ है। 2018 के विधानसभा चुनावों के बाद भाजपा ने

अपने प्रदेश अध्यक्ष को तीन बार बदला है और पिछले वर्ष विधानसभा में अपने नेता प्रतिपक्ष को भी बदल दिया है। भाजपा ने रमन सिंह को भी लगभग दरकिनार कर दिया है, जो 2013 से 2018 के बीच मुख्यमंत्री रहे। इनके कार्यकाल में सरकार पर नागरिक आपूर्ति घोटाले और चिट फंड घोटाले का आरोप लगा। राज्य में कांग्रेस लगातार भाजपा पर निशाना साध रही है और दावा कर रही है कि उसके केंद्रीय नेतृत्व को राज्य में पार्टी के अग्रिम पंक्ति के नेताओं पर भरोसा नहीं है।

कांग्रेस के खिलाफ जो मुद्दे जा सकते हैं अगर उसकी बात करें तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण सहित अधूरे वादे विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में लोगों के क्रोध का कारण बन सकते हैं। 'मोदी फैक्टर' जो भाजपा को प्रतिद्वंद्वी पार्टियों पर बढ़त दिलाता है। आम आदमी पार्टी (आप) और सर्व आदिवासी समाज (आदिवासी संगठनों का एक समूह) के चुनाव में ताल ठोंकने से कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लग सकती है। हम आपको बता दें कि वर्ष 2018 में चुने गए 68 कांग्रेस विधायकों में से कुल 35 पहली बार चुने गए थे और उनमें से अधिकांश अब अपने प्रदर्शन को लेकर जनता के विरोध का सामना कर रहे हैं। वैसे छत्तीसगढ़ में आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सबसे प्रमुख राजनीतिक दल माने जाते हैं। राज्य में कुछ अन्य राजनीतिक दल भी हैं लेकिन उनका प्रभाव कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है। आदिवासी समुदायों की संस्था 'सर्व आदिवासी समाज' के चुनाव मैदान में आने से इस बार का चुनाव दिलचस्प हो सकता है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इससे ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में सत्ताधारी दल को नुकसान हो सकता है। राज्य में आदिवासियों के हितों के लिए काम करने वाली गोंडवाना गणतंत्र पार्टी (जीजीपी) भी चुनाव मैदान में है। हम आपको बता दें कि राज्य की आबादी में लगभग 32 प्रतिशत हिस्सेदारी जनजातीय समुदाय की है।

दूसरी ओर राज्य में भाजपा की बात करें तो आपको बता दें कि पार्टी अब चुनावी रणनीति के तहत सरकार को भ्रष्टाचार और कुशासन के मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रही है। भाजपा अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता पर भरोसा कर रही है। वहीं पार्टी के

भाजपा की कमजोरियों की बात करें तो आपको बता दें कि कई निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा के पास मजबूत संगठनात्मक ढांचे का अभाव है और सभी 119 विधानसभा सीटों पर मजबूत उम्मीदवार न होना भी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसके अलावा स्थानीय ईकाई की प्रत्येक फैसले के लिए केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भरता है। लोगों के बीच यह प्रबल भावना है कि भाजपा और बीआरएस के बीच एक मौन साझेदारी है। बंदी संजय को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाना एक कमजोरी के रुप में देखा जाता है। राज्य इकाई में ऐसा कोई नेता नहीं है जो मुख्यमंत्री केसीआर के कद का मुकाबला कर सके।

स्टार प्रचारक राज्य में अपनी यात्राओं के दौरान कई मुद्दों, विशेषकर भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस सरकार पर खुलकर हमले कर रहे हैं। कुछ महीने पहले तक भाजपा की राज्य इकाई जो गुटबाजी से ग्रस्त दिखाई दे रही थी पिछले कुछ महीनों में आक्रामक हो गई है। राज्य में चुनाव के करीब आते ही भाजपा के रणनीतिकार अमित शाह ने यहां कई बैठकें की है तथा प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में अच्छी भीड़ ने पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया है। पिछले तीन महीनों में अपनी चार रैलियों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कोयला, शराब, गोबर खरीद और जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) फंड के उपयोग सहित हर क्षेत्र और सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार तथा कथित घोटालों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री ने भाजपा के सत्ता में आने पर भर्ती परीक्षा आयोजित करने वाले राज्य लोक सेवा आयोग (पीएससी) में कथित घोटाले की जांच कराने का भी वादा किया है। इधर, भाजपा ने यह भी आरोप लगाया है कि आदिवासी बहुल इलाकों में धर्मांतरण हो रहा है तथा दावा किया कि

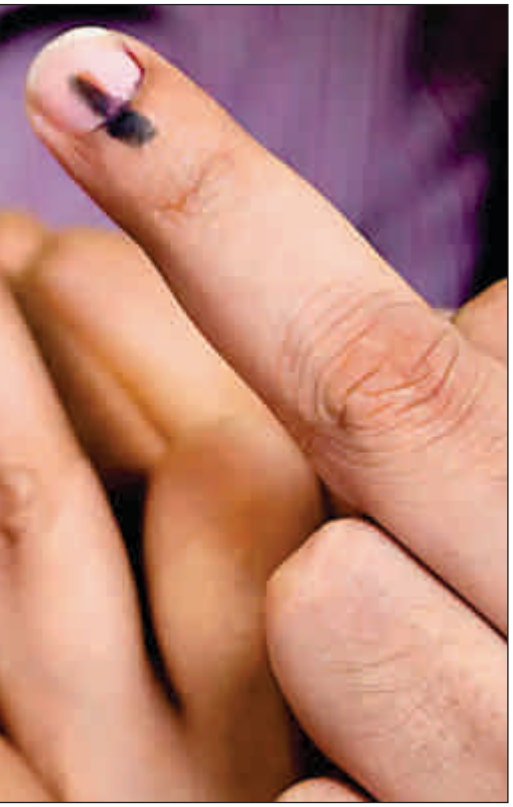

सरकार उन पर अंकुश लगाने में विफल रही है। राज्य में भाजपा ने अब तक 21 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जबकि सत्ताधारी दल कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। दोनों प्रमुख दलों ने कहा है कि वे सामूहिक नेतृत्व के आधार पर चुनाव लड़ेंगे, न कि किसी एक राजनेता के चेहरे पर। हम आपको बता दें कि पिछले चुनाव में कांग्रेस ने विधानसभा की कुल 90 सीटों में से 68 सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा 15 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही थी। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी द्वारा स्थापित जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) को पांच सीटें मिली थीं और उसकी सहयोगी बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने दो सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस को 2018 में 43.04 प्रतिशत मत मिले थे, जो भाजपा (32.97 प्रतिशत) से लगभग 10 प्रतिशत अधिक था।

तेलंगाना

माना जा रहा है कि तेलंगाना विधानसभा के लिए होने वाले चुनावों के लिए प्रचार अभियान के दौरान तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग (टीएसपीएससी) की परीक्षाओं से जुड़े प्रश्नपत्र लीक मामले के अलावा दिल्ली आबकारी नीति मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की विधान परिषद सदस्य के कविता पर लगे आरोपों, बीआरएस सरकार के 'धरणी' भूमि रिकॉर्ड पोर्टल से संबंधित शिकायतों और राज्य सरकार की कथित विफलताओं का मुद्दा छाया रह सकता है। वहीं, बीआरएस मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करने के वास्ते विकास और जनकल्याण के अपने 'तेलंगाना मॉडल' को प्रचारित करना जारी रखेगी। देखा जाये तो तेलंगाना में नौकरियों की कमी एक प्रमुख मुद्दा है, क्योंकि युवाओं ने नये राज्य में नौकरियां हासिल करने की उम्मीद के साथ अलग प्रदेश के गठन के लिए लड़ाई लड़ी थी। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का आरोप है कि बीआरएस सरकार 'हर परिवार को नौकरी देने का अपना वादा' निभाने में नाकाम रही है। दोनों पार्टियों का दावा है कि बीआरएस सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान पर्याप्त भर्तियां न करके तेलंगाना के युवाओं को निराश किया है। वे टीएसपीएससी द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने के लिए भी सरकार को कसूरवार ठहरा रही हैं। प्रश्नपत्र लीक की घटनाओं ने तेलंगाना को हिलाकर रख दिया था। कांग्रेस और भाजपा ने इस साल मार्च और अप्रैल के दौरान बीआरएस सरकार के खिलाफ कई विरोध-प्रदर्शन किए थे। दोनों दलों ने बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के अपने चुनावी वादे को पूरा नहीं करने के लिए भी बीआरएस सरकार की आलोचना की थी।

इसके अलावा, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में सत्तारुढ़ पार्टी की विधान परिषद सदस्य और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता पर लगे आरोपों के संबंध में बीआरएस और भाजपा के बीच एक मौन सहमति है। हम आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में कविता से भी पूछताछ की है, जिससे कांग्रेस और भाजपा को मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली बीआरएस सरकार पर हमला करने का एक हथियार मिल गया। यही नहीं, एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली 'धरणी' को लेकर भी बीआरएस सरकार को कांग्रेस और भाजपा की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है। ऐसे में प्रचार अभियान के दौरान 'धरणी' के खराब कार्यान्वयन का मुद्दा भी प्रमुखता से उठने की उम्मीद है। कांग्रेस ने 'धरणी' को लेकर सरकार पर भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और विफलताओं का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया है कि बड़ी संख्या में छोटे और सीमांत किसानों के परिवारों के भूमि रिकॉर्ड को ऑनलाइन प्रणाली में शामिल नहीं किया गया है।

तेलंगाना में विरोधी दल जिन अन्य मुद्दों को लेकर बीआरएस सरकार को निशाना बना सकते हैं, उनमें गरीबों के लिए दो बेडरूम वाले घर बनाने, 'हर परिवार को नौकरी देने' और दलितों का कल्याण सुनिश्चित करने के पार्टी के चुनावी वादे शामिल हैं। कांग्रेस और भाजपा का मानना है कि बीआरएस सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान प्राप्त आवेदनों की संख्या की तुलना में गरीबों के लिए कम दो बेडरूम वाले घर बनाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीआरएस की प्रमुख दलित कल्याण योजना 'दलित बंधु' से जमीनी स्तर पर ज्यादातर लोगों को लाभ नहीं हुआ। वहीं, भाजपा का दावा है कि बीआरएस सरकार का वादे के मुताबिक दलितों को तीन एकड़ जमीन वितरित करने में नाकाम रहना भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा होगा।

हम आपको यह भी बता दें कि हाल ही में कांग्रेस ने हैदराबाद में एक जनसभा के दौरान तेलंगाना के लिए छह चुनावी 'गारंटी' की घोषणा की थी। पार्टी इन घोषणाओं के जरिये जमीनी स्तर के मतदाताओं के बीच पैठ बनाना चाहती है। पड़ोसी राज्य कर्नाटक में किए गए इसी तरह के वादों के बलबूते कांग्रेस को इस साल मई में वहां आयोजित विधानसभा चुनावों में भाजपा को करारी शिकस्त देने और सत्ता में वापसी करने में मदद मिली थी।

दूसरी ओर, बीआरएस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने जोर देकर कहा है कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में तेलंगाना देश में शीर्ष पर है। पार्टी नेता बीआरएस सरकार में राज्य में हुई प्रगति को दर्शाने के लिए अक्सर 'मिशन भगीरथ' का जिक्र करते हैं, जिसके तहत घरों में पाइप से पीने के पानी की आपूर्ति की जाती है। राज्य सरकार ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री राव के दिमाग की उपज इस पहल के तहत हर घर में पाइप से पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी, किसानों के लिए 'रायथु बंधु' निवेश सहायता योजना और 'रायथु बीमा' जीवन बीमा योजना, 'कल्याण लक्ष्मी' एवं 'शादी मुबारक' जैसी विवाह सहायता योजना तथा कृषि क्षेत्र को

हफ्ते में सातों दिन चौबीस घंटे मुफ्त बिजली आपूर्ति उन योजनाओं में शामिल है, जिनके जरिये बीआरएस अपनी उपलब्धियां गिनाने की कोशिश करेगी। बीआरएस केंद्र में सत्तारुढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) और भाजपा की कथित सांप्रदायिक राजनीति तथा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत तेलंगाना से किए गए वादों को पूरा नहीं करने को लेकर बेहद आलोचनात्मक रही है।

तेलंगाना में भाजपा की बात करें तो पिछले तीन साल में कुछ उपचुनाव और वृहद हैदराबाद नगर निगम चुनाव जीतने के बाद आंतरिक कलह का सामना करना पड़ा। अंसतुष्टों को शांत करने की कवायद के रूप में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के स्थान पर बंदी संजय कुमार को हटाकर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को नियुक्त करना पड़ा। भाजपा की ताकत, कमजोरियों, अवसरों और चुनौतियों का विश्लेषण करने के दौरान अगर भाजपा की ताकत के बारे में बात करें तो राज्य में पार्टी द्वारा बरकरार साफ छवि उसे फायदा पहुंचा सकती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता और राज्य में पार्टी की राजनीतिक स्फूर्ति उसकी ताकत बन सकती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरआरएस) से संबद्ध विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और बजरंग दल जैसे संघ परिवार से समर्थन मिलेगा।

भाजपा की कमजोरियों की बात करें तो आपको बता दें कि कई निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा के पास मजबूत संगठनात्मक ढांचे का अभाव है और सभी 119 विधानसभा सीटों पर मजबूत उम्मीदवार न होना भी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसके अलावा स्थानीय ईकाई की प्रत्येक फैसले के लिए केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भरता है। लोगों के बीच यह प्रबल भावना है कि भाजपा और बीआरएस के बीच एक मौन साझेदारी है। बंदी संजय को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाना एक कमजोरी के रूप में देखा जाता है। राज्य इकाई में ऐसा कोई नेता नहीं है जो मुख्यमंत्री केसीआर के कद का मुकाबला कर सके।

भाजपा के लिये अवसरों की बात करें तो पार्टी कुछ उपलब्धियों पर दावा जता सकती है जैसे कि महिला आरक्षण विधेयक पारित होना और 17 सितंबर को तेलंगाना मुक्ति दिवस के रूप में मनाना। वह सत्तारुढ़ गठबंधन में स्थानीय नेतृत्व के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को भी उठा सकती है।

राजस्थान में पिछले लगभग तीन दशक से हर विधानसभा चुनाव में 'सरकार' बदलने की 'परिपाटी' है और यहां एक बार फिर सत्तारुढ़ कांग्रेस व विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधा मुकाबला रहने की संभावना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पिछले महीने कहा था कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव में मुकाबला "बहुत करीबी" रहेगा। यह कहते हुए उन्होंने एक तरह से संकेत दिया कि वह राजस्थान में अपनी पार्टी के दोबारा सरकार बनाने को लेकर अन्य राज्यों की तुलना में अधिक आश्वस्त नहीं हैं। राज्य की 'परिपाटी' को देखते हुए हो सकता है कि कांग्रेस नेता का यह आकलन सही साबित हो।

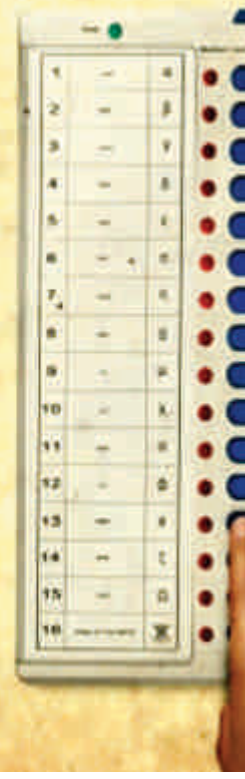

केसीआर की बेटी कविता की दिल्ली आबकारी घोटाले मामले में कथित भूमिका का मुद्दा भी उठा सकती है।

भाजपा की चुनौतियों की बात करें तो कर्नाटक चुनाव के बाद उसकी राष्ट्रीय प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस तेलंगाना में बीआरएस के एक विकल्प के रूप में उभरी है। इसके परिणामस्वरूप सत्ता विरोधी वोट कांग्रेस के पाले में जा सकते हैं। कांग्रेस का प्रचार अभियान भाजपा और बीआरएस के बीच कथित मौन साझेदारी के इर्द-गिर्द हो सकता है। भाजपा को इससे प्रभावी रूप से निपटने की आवश्यकता है। कांग्रेस अपने प्रमुख चुनावी मुद्दों में से एक के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकती है। इसके अलावा, सभी 119 निर्वाचन क्षेत्रों में मजबूत नेतृत्व का अभाव है। कुछेक नेताओं को छोड़कर पार्टी में लोगों को आकर्षित करने वाले नेताओं की कमी है। इसके अलावा, यह भी देखने को मिलता है कि तेलंगाना में सत्तारुढ़ भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) को 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान सत्ता विरोधी लहर से जूझना पड़ सकता है जबकि नए रूप और आत्मविश्वास में नजर आ रही कांग्रेस और आक्रामक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उसे चुनौती देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। बीआरएस निवेश और कानून-व्यवस्था के क्षेत्र में अपने ट्रैक रिकॉर्ड पर सवार होकर चुनावी जीत की हैट्रिक लगाना चाहेगी। पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के नाम से जानी जाने वाली मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली बीआरएस को साल 2014 (अविभाजित आंध्र प्रदेश में) और फिर 2018 में हुए चुनाव में जीत हासिल हुई थी। विपक्षी दलों ने विभिन्न सरकारी परियोजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं।

बीआरएस की मजबूती की बात करें तो केसीआर को तेलंगाना के लिए राज्य का दर्जा दिलाने वाले एकमात्र व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता है। रायतू बंधु और केसीआर किट्स जैसी कुछ सरकारी योजनाओं से उनका समर्थन बढ़ा है। उनकी सरकार बनने के बाद से राज्य में ग्रामीण और शहरी बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य देखभाल में उल्लेखनीय बदलाव आया है। चुनाव कार्यक्रम जारी होने से पहले ही पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई, जिससे बीआरएस उम्मीदवारों को बढ़त मिल गई। बीआरएस सरकार को

निवेशकों के लिहाज से अनुकूल माना जाता है, और राज्य में पार्टी के पिछले नौ वर्ष के शासन में भारी निवेश हुआ है। केसीआर ने एक स्थिर सरकार का नेतृत्व किया है, जिसका राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने का ठोस ट्रैक रिकॉर्ड है। हैदराबाद में राज्य की कुल आबादी का लगभग एक-चौथाई हिस्सा रहता है, इस शहर को केसीआर के बेटे और आईटी मंत्री केटी रामा राव की प्रत्यक्ष देखरेख में एक वैश्विक शहर के रूप में मान्यता मिली है। पिछले नौ वर्षों में पार्टी का संगठनात्मक ढांचा जमीनी स्तर पर मजबूत हुआ है। बीआरएस के पास धन की कोई कमी नहीं है। पार्टी के पास अल्पसंख्यक वोटों का ठोस आधार है।

बीआरएस की कमजोरियों की बात करें तो पार्टी के कई मौजूदा विधायक पार्टी के भीतर सत्ता विरोधी लहर और असंतोष का सामना कर रहे हैं। केसीआर पर लगे 'पारिवारिक शासन' के आरोप और उनकी बेटी के. कविता के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप चुनावी मुद्दा बन सकते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की शानदार जीत ने राजनीतिक कहानी बदल दी है, जिसे लेकर पार्टी आत्मविश्वास से भरी हुई है, वहीं कर्नाटक में हार से आहत भाजपा उतनी ताकतवर नहीं दिख रही है। इससे वोटों का विभाजन कम होने पर विरोधी वोट कांग्रेस के खाते में जा सकते हैं।

बीआरएस के पास अवसरों की बात करें तो विपक्षी दलों का अपेक्षाकृत कमजोर होना बीआरएस को एक अवसर दे सकता है क्योंकि कांग्रेस से जुड़े कई नेताओं और विधायकों ने पाला बदल लिया है। कांग्रेस और भाजपा दोनों अंतर्कलह से जूझ रही हैं। भाजपा ने वह लय खो दी जो पार्टी के पूर्व प्रमुख बी. संजय कुमार ने बनाई थी। उनकी जगह केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी को लाया जाना स्थानीय स्तर पर पार्टी के लिए कमजोरी के रूप में देखा जा रहा है। यदि विपक्षी वोट कांग्रेस और भाजपा के बीच समान रूप से विभाजित हो जाता है, तो त्रिकोणीय मुकाबला बीआरएस के लिए फायदेमंद होगा।

बीआरएस की चुनौतियों पर बात करें तो अडिग भाजपा और उसका सख्त नेतृत्व बीआरएस के

हाल ही में गहलोत के निर्वाचन क्षेत्र सरदारपुरा जोधपुर में हुई। मोदी ने इस जनसभा में पिछले साल जोधपुर में हुई सांप्रदायिक हिंसा का जिक्र करते हुए कांग्रेस सरकार पर "तुष्टिकरण" का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को राजस्थान के हित से ज्यादा अपना वोट बैंक प्यारा है।

राज्य में भाजपा की चुनाव रणनीति में "तुष्टिकरण" और हिंदुत्व अपील प्रमुख कारक हो सकता है। भाजपा कानून-व्यवस्था, खासकर महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर भी राज्य सरकार पर निशाना साधती रही है। और फिर कथित "लाल डायरी" का मामला है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि इसमें वित्तीय अनियमितताओं का विवरण था। गहलोत मंत्रिमंडल के बर्खास्त सदस्य राजेंद्र गुढ़ा का दावा है कि यह उनके पास है। राज्य के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) द्वार भी कुछ सीटों उम्मीदवार खड़े करने की उम्मीद है। लेकिन इतिहास के हवाले से विश्लेषक मानते हैं कि राजस्थान के विधानभा चुनाव दरअसल दो ही पार्टियों की 'दौड़' है। 2018 के विधानसभा चुनावों में 199 सीटों में से कांग्रेस को 99 व भाजपा को 73 सीटें मिलीं। अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट पर बसपा प्रत्याशी के निधन के बाद चुनाव स्थगित कर दिया गया जो 28 जनवरी को हुआ। इसमें भी कांग्रेस ने बाजी मारी। वहीं अगले साल 2019 में लोकसभा चुनाव में भाजपा को 25 में से 24 सीटें मिलीं। बाकी एक सीट उसकी सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के पास चली गई।

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा हो चुकी है। नवंबर में 17 तारीख को होने वाले चुनाव में यहां दस मुद्दों के प्रचार परिदृश्य पर हावी होने की संभावना है और ये मुद्दे 230 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव के नतीजे तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मप्र में सत्तारुढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस सत्ता के मुख्य दावेदार बने रहेंगे, हालांकि आम आदमी पार्टी (आप) और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) जैसे संगठन अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में भारतीय राजनीति की दो दिग्गज पार्टियों (भाजपा और कांग्रेस) के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और कड़ी टक्कर देने की कोशिश करेंगे। वर्ष 2018 में आखिरी चुनावों के बाद, राज्य में मार्च 2020 में तब सत्ता परिवर्तन देखने को मिला जब अनुभवी राजनेता कमल नाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिर गई और भाजपा सिर्फ 15 महीने तक विपक्ष में रहने के बाद सत्ता में वापस आ गई। दिसंबर 2018 से मार्च 2020 तक की 15 महीने की अवधि को छोड़कर (जब कांग्रेस सत्ता में थी), भाजपा को लगभग चार कार्यकालों की सत्ता-विरोधी लहर से पार पाने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर, कांग्रेस कई मुद्दों पर शिवराज सिंह चौहान सरकार के खिलाफ लोगों के बीच नाराजगी को भुनाने की कोशिश करेगी। 1. नरेन्द्र मोदी: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रचार परिदृश्य पर हावी रहेंगे और भाजपा के तुरुप का इक्का बने रहेंगे। भाजपा एक और चुनावी जीत हासिल करने के लिए मोदी की शक्तिशाली वाक् कला, राजनीतिक करिश्मा, स्थायी जन अपील और लोकप्रियता पर बहुत अधिक निर्भर करेगा। 2. भ्रष्टाचार/घोटाले: कांग्रेस मौजूदा भाजपा शासन में कथित भ्रष्टाचार को अपना मुख्य चुनावी मुद्दा बनाने जा रही है। विपक्षी दल ने दावा किया है कि जब भाजपा सत्ता में थी तो कर्नाटक में 40 फीसदी कमीशन की सरकार थी, लेकिन मध्य प्रदेश में 50 फीसदी कमीशन की सरकार है। कुछ महीने पहले कांग्रेस ने प्रदेश भर में शिवराज चौहान सरकार पर 50 फीसदी कमीशनखोरी का आरोप लगाते हुए पोस्टर चिपकाए थे। कांग्रेस ने उज्जैन में 'महाकाल लोक' के निर्माण में भी भारी अनियमितता का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने भाजपा शासन के 18 साल के दौरान 250 से ज्यादा बड़े घोटाले भी गिनाए हैं। वित्तीय घोटालों की सूची में व्यापमं भर्ती और प्रवेश घोटाला सबसे ऊपर है।

3. सत्ता विरोधी लहर: भाजपा मध्य प्रदेश में 2003 से 15 महीने की अवधि (दिसंबर 2018-मार्च 2020) को छोड़कर सत्ता में है और सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रही है। इन 15 महीनों में कांग्रेस का शासन मप्र में था। भाजपा शासन के सभी वर्षों में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पार्टी का चेहरा बने रहे। रणनीति में बदलाव करते हुए, भाजपा ने राज्य में तीन केंद्रीय मंत्रियों और चार संसद सदस्यों को मैदान में उतारा है, इस कदम को चार बार के मुख्यमंत्री चौहान के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर को कुंद करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। इतने सारे वरिष्ठ भाजपा नेताओं की मौजूदगी ने मुख्यमंत्री पद के दावेदारों के लिए मैदान खुला छोड़ दिया है।

4. सिंधिया समर्थकों का भाग्य: केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के वास्ते अपने सभी प्रमुख समर्थकों के लिए चुनाव टिकट प्राप्त करना एक कठिन काम होगा, जो 2020 में कांग्रेस छोड़कर उनके साथ भाजपा में शामिल हो गए। उन सभी को समर्पित भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की कीमत पर समायोजित करना होगा जो कि निश्चित रूप से नाराजगी पैदा करेगा। 5. अपराध: बढ़ता अपराध ग्राफ, विशेषकर महिलाओं और दलितों और आदिवासियों सहित कमजोर वर्गों के सदस्यों के खिलाफ घटनाएं, मतदाताओं के बीच एक प्रमुख मुद्दा है। सीधी जिले में एक व्यक्ति द्वारा एक आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब करने की घटना ने राज्य को झकझोर कर रख दिया। क्षति नियंत्रण के प्रयास में मुख्यमंत्री चौहान ने आदिवासी व्यक्ति के पैर धोए और उससे माफी मांगी। 6. प्रोजेक्ट चीता: मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में छह चीतों और तीन शावकों की मौत ने दुनिया के जमीन पर सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर को देश में फिर से लाने के कार्यक्रम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुनरुद्धार कार्यक्रम लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। संरक्षणवादियों के एक वर्ग ने पूरी परियोजना की कल्पना और कार्यान्वयन के तरीके पर सवाल उठाया है।

7. किसान: राज्य में कृषि संबंधी मुद्दे हमेशा राजनीतिक चर्चा में हावी रहे हैं और सभी दलों ने किसानों को लुभाने की कोशिश की है। सत्ता में रहने के दौरान कांग्रेस और भाजपा दोनों ने कृषि ऋण माफी के मुद्दे पर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया है। गुणवत्तापूर्ण बीजों की अनुपलब्धता और उर्वरकों की कमी किसानों के लिए प्रमुख चिंता का विषय रही है। 8. बेरोजगारी: युवाओं के बीच बेरोजगारी की उच्च दर एक चुनौती बनी हुई है और मतदाताओं के लिए शीर्ष मुद्दों में से एक है। बेरोजगार युवाओं का दिल जीतने के लिए आप ने सत्ता में आने पर बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया

है। दूसरी ओर, भाजपा सरकार युवाओं में कौशल विकसित करने और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने की कोशिश कर रही है।

9. शिक्षा और स्वास्थ्य: दोनों का आम नागरिकों और उनके समग्र कल्याण से गहरा संबंध है। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में स्कूल खोले गए हैं, लेकिन योग्य शिक्षकों की कमी है, और यदि शिक्षक उपलब्ध हैं, तो छात्रों को उचित शिक्षा प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे की कमी है। इन चुनावों में अस्थायी शिक्षकों का नियमितीकरण एक बड़ा मुद्दा है। छोटे शहरों के अधिकांश अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त प्रशिक्षित कर्मचारियों, विशेषकर डॉक्टरों की कमी है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 10. मुख्यमंत्री चेहरा: जबकि कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसके अनुभवी नेता कमल नाथ पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा हैं, वहीं मुख्यमंत्री चौहान राज्य के नेताओं में सबसे लोकप्रिय व्यक्ति बने हुए हैं, इसके बावजूद भाजपा इस मामले पर स्पष्ट नहीं है। ■

भारत में राष्ट्रवादी राजनीति ही अब सभी दलों की नियति

16वीं लोकसभा के चुनाव से ही देश भर में आम जनता के बीच भाजपा के बढते स्वीकार और कांग्रेस व उसके सहयोगी दलों के प्रति बडी तेजी से बढते नकार को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इसका मूल कारण वतुत: साम्प्रदायिक अल्पसंख्यक तुष्टिकरणवादी राष्ट्रघाती राजनीति के विरुद्ध धार्मिक बहुसंख्यक राष्ट्रीयतावादी राजनीति का उभार है, जो स्वतंत्रता-संघर्ष काल से ही कुहियाते-सुलगते हुए अब आकर चुनावी लोकतंत्र में आकार ग्रहण किया है ।

मनोज ज्वाला

भारत गणराज्य का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बडा लोकतंत्र है । कई अर्थों में यह अन्य देशों के लोकतंत्र से विशिष्ट भी है। अब इसमें एक और विशिष्टता जुड चुकी है। वह यह कि यहां सांवैधानिक रुप से तकनीकी तौर पर विपक्ष समाप्त हो चुका है । भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रत्यक्षतः अभिव्यक्त करने वाली संसद के दोनों सदनों में जो सबसे बडा सदन है 'लोकसभा' सो विपक्ष-विहीन है। सत्ता-पक्ष के तमाम विरोधी दलों में से कोई भी दल कायदे से विपक्ष नहीं है। विपक्ष होने के लिए किसी भी दल के पास लोकसभा के जितने सदस्यों की संख्या चाहिए वह कोई भी प्रतिपक्षी दल नहीं जुटा पा रहा है। १६वीं लोकसभा के चुनाव-परिणामस्वरुप देश की केन्द्रीय सत्ता से बेदखल हो कर विपक्ष में बैठी कांग्रेस वस्तुतः विपक्ष थी ही नहीं , क्योंकि वह इस बावत संसद-सदस्यों की निर्धारित न्यूनतम संख्या की अर्हता पूरी नहीं कर सकी थी। वर्तमान १७वीं लोकसभा में भी विरोधी दलों के बीच सबसे बडी हैसियत रखने वाली कांग्रेस कायदे से विपक्ष नहीं बन सकी है, क्योंकि उसके सांसदों की संख्या पिछली बार से बढने के बावजूद निर्धारित न्यूनतम अर्हता को नहीं छू सकी है। हालाकि संसद की राज्य सभा में किसी तरह से विपक्ष बनी हुई है कांग्रेस, किन्तु चूंकि वह उच्च सदन है, जिसके सदस्य सीधे आम जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं होते हैं , बल्कि प्रान्तीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चयनित होते हैं ; इस कारण लोकतंत्र के प्रत्यक्ष अभिव्यक्त होने की दृष्टि से उसका कोई खास मतलब नहीं है। जबकि वहां भी सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद उसका आकार घटना और सत्ता-पक्ष का आकार बढना सुनिश्चित है। ऐसा इस कारण, क्योंकि देश की अधिकतर विधानसभाओं में भी कांग्रेस की

हालत बहुत पतली है । शेष विरोधी दलों की स्थिति तो उससे भी खराब है। देश के भीतर अनेक व सर्वाधिक प्रदेशों में भी केन्द्रीय सत्ता पर आरुढ भाजपा की ही सरकारें हैं । भाजपा-विरोधी दलों की जहां-जहां जो सरकारें हैं भी , वे सब डांवाडोल स्थिति में हैं। बहुमत का ऐसा टोंटा है कि वे कभी भी गिर सकती हैं । वहां की विधानसभाओं में अफरा-तफरी व भागा-भागी मची हुई हैं । उन तमाम गैर-भाजपाई दलों से समूह के समूह विधायक भाजपा में शामिल होते रहे हैं। कांग्रेसी नेताओं-कार्यकर्तओं को भी कदाचित ऐसा प्रतीत होने लगा है कि कांग्रेस एकबारगी मिट ही जाएगी। यह स्वाभाविक भी है , क्योंकि कांग्रेस लगातार सिमटती ही जा रही है । न केवल कांग्रेस का बल्कि , अन्य दूसरे विरोधी दलों, जो प्रकारान्तर में कांग्रेस की ही ऊपज हैं, उनका भी कमोबेस यही हाल है। बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस इसी तरह के संकट से जूझ रही है। उधर तमिल-तेलगू प्रदेशों में भी भाजपा का आकार बढता जा रहा है। उतर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सहित लगभग सभी उन दलों को जनता नकार चुकी है और लगातार नकारती जा रही है , जो भाजपा पर साम्प्रदायिक होने का ठप्पा लगाते हुए स्वयं धर्मनिरपेक्षता के झण्डाबरदार बन बहुसंख्यक हिन्दू-समाज के विरुद्ध तथाकथित अल्पसंख्य सम्प्रदायों के तुष्टिकरण की राजनीति करते रहे हैं। इस धर्मनिरपेक्षता बनाम साम्प्रदायिक तुष्टिकरणवादिता की आंच पर सत्ता की रोटी सेंकते-खाते रहने वाले इन तमाम गैर-भाजपाई दलों की राजनीति असल में राष्ट्रनीति पर भी हावी होती जा रही थी, जिसके कारण देश के भीतर-बाहर दोनों तरफ राष्ट्रीय हितों का हनन होता रहा था।

१६वीं लोकसभा के चुनाव से ही देश भर में आम जनता के बीच भाजपा के बढते स्वीकार और कांग्रेस व उसके सहयोगी दलों के प्रति बडी तेजी से बढते नकार को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इसका मूल कारण वतुतः साम्प्रदायिक अल्पसंख्यक तुष्टिकरणवादी राष्ट्रघाती राजनीति के विरुद्ध धार्मिक बहुसंख्यक राष्ट्रीयतावादी राजनीति का उभार है, जो स्वतंत्रता-संघर्ष काल से ही कुहियाते-सुलगते हुए अब आकर चुनावी लोकतंत्र में आकार ग्रहण किया है। यह राष्ट्रीयता का उभार जो है, सो असल में भारत के उस सांस्कृतिक पुनरुत्थान का उभार है, जिसके बावत महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी महर्षि अरविन्द ने कहा था कि सनातन धर्म ही भारत की राष्ट्रीयता

है। स्वामी विवेकानन्द ने इसी को हिन्दुत्व कहा , जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनाया हुआ है। इस हिन्दुत्व से निःसृत राजनीति को ही भाजपा ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रुप में अपनी राजनीति का आधार बनाया , जिसके तहत भारत के सांस्कृतिक पुरुषों-प्रतीकों-परम्पराओं की पुनर्प्रतिष्ठा तथा समान नागरिक संहिता और साम्प्रदायिक तुष्टिकरण के बाजाय सर्वपंथ समभाव की अवधारणा पेश कर कांग्रेसी खेमे के समक्ष जो चुनौतियां पेश की उसका मुकाबला वे नहीं कर सके । धर्मनिरपेक्षता के उन झण्डाबरदारों ने अल्पसंख्यकवाद की अपनी छद्म दुर्नीति के तहत जिस भाजपा को राजनीतिक अछुत घोषित कर उसकी राह रोकने के लिए परस्पर गठबन्धन कायम कर रखा था, उस भाजपा को जनता से इतना समर्थन प्राप्त हुआ कि सन २०१४ के आमचुनाव में वह उन सबको न केवल सत्ता से बेदखल कर दी, बल्कि विपक्ष बनने के लायक भी नहीं रहने दी । फिर तो वे बुरी तरह से पिट चुकी हिन्दुत्व-विरोधी धर्मनिरपेक्षता का सिक्का पुनः चलाने के लिए जिन-जिन हथकण्डों का इस्तेमाल किये , सो सब इस कदर उल्टा प्रभाव देते गए कि १७वीं लोकसभा के चुनाव में उनके 'महागठबन्धन' को भी जनता ने मटियामेट कर हिन्दुत्व-प्रेरित राष्ट्रवादी राजनीति पर ही मुहर लगा दी।

ऐसे में जाहिर है; संसद की दस प्रतिशत सिटों से भी वंचित रह गई कांग्रेस एवं उसके सहयोगियों को सत्ता के शिखर तक पहुंचने के लिए ही नहीं, बल्कि विपक्ष की जमीन हासिल करने के लिए भी राष्ट्रवादी राजनीति का अनुसरण तो करना ही होगा। बहुसंख्यक-विरोधी अल्पसंख्यकवादी धर्मनिरपेक्षतावाद का परित्याग किये बगैर 'संविधान व लोकतंत्र की रक्षा' का बेजान-बेतुका नारा लगाते रहने तथा सत्ता-पक्ष का विरोध के नाम पर भारत की एकता-अखण्डता-सम्प्रभुता व राष्ट्रीयता के विरोध में ही उतर आने और 'सहिष्णुता-असहिष्णुता' की माप-तौल करते रहने अथवा 'मौब लिंचिंग' जैसे नये-नये शब्दों का ईजाद करने या जनता को काल्पनिक भय से भयभीत करने जैसे हथकण्डों के सहारे उनका राजनीतिक उन्नयन दूर की कौडी प्रतीत होता है। क्योंकि, तत्वदर्शी भविष्यवेत्ता विवेकानन्द व महर्षि अरविन्द से ले कर युगऋषि आचार्य श्रीराम शर्मा तक ने भारत के राष्ट्रीय पुनरुत्थान की सुनिश्चित भवितव्यता और उसके फलित होने की जिस कालबद्धता का संकेत किया हुआ है , उसका दौर सन २०११ से ही शुरू हो चुका है। जनता का तदनुसार मानसिक-बौद्धिक परिष्कार एक दिव्य चेतना की प्रेरणा से अब स्वतः होने लगा है। ऐसे में राष्ट्रवादी राजनीति ही अब 'विपक्ष' की भी विवशता-जनित नियति है । भाजपा भी यदि राष्ट्रवाद से विमुख हो जाएगी, तो उसकी भी वही गति होगी, जो आज उसके विरोधियों की त्रासदी है । ऐसा इस कारण, क्योंकि किसी भी देश के बहुसंख्यक समाज की सांस्कृतिक भावना-विचारणा ही उस देश की राष्ट्रीयता होती है और उस राष्ट्रीयता को तिरस्कृत कर कोई भी शक्ति लम्बे समय तक उस पर शासन कतई नहीं कर सकती है। भारतीय राजनीति के केन्द्र में भारत की सनातन राष्ट्रीयता जो निश्चित रुप से हिन्दुत्व ही है, सो स्थापित हो चुकी है ; अतएव उस परिधि से बाहर की राजनीति पर चलने वाले दल इसी तरह से खारिज होते रहेंगे। ■

विराट सांस्कृतिक चेतना की पुनर्स्थापना का संकल्प

एक भारत श्रेष्ठ भारत

'एक भारत श्रेष्ठ भारत' कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक गतिविधियां की जाती हैं। इसके अंतर्गत पांच पुरस्कार विजेता पुस्तकों और कविता, लोकप्रिय लोकगीतों का एक भाषा से भागीदार राज्य की भाषा में अनुवाद किया गया है। साझेदार राज्यों की पाक पद्धतियों को सीखने के लिए पाक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। साझेदार राज्यों से आने वाले आगंतुकों के लिए होमस्टे की व्यवस्था की गई है। पर्यटकों के लिए राज्य दर्शन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।

डॉ. सौरभ मालवीय

भारत एक विशाल राष्ट्र है। इसका निर्माण सनातन संस्कृति से हुआ है। अनेक संस्कृतियां भारत रूपी गुलदान में विभिन्न प्रकार के पुष्पों की भांति रही हैं। इसका अर्थ यह है कि इन विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं, धर्मों एवं पंथों आदि ने इस देश के सांस्कृतिक सौन्दर्य में वृद्धि की है। यहां विविधता में भी एकता है। भारत शान्ति-प्रिय देश है। यह अहिंसा में विश्वास रखता है। परन्तु देश में गुलामी एवं संघर्षों के बाद आजादी से लेकर एक लंबे कालखंड तक 'बांटो और राज करो' की नीति पर चलते हुए समाज, जाति, पंथ, मत, मजहब, खान-पान, वेशभूषा आदि के आधार पर विभाजन जारी रहा। इसके परिणाम स्वरूप देश की सांस्कृतिक प्रतिष्ठा पर गंभीर कुठाराघात हुआ। भारत में हिंदूकुश से हिंद महासागर तक फैली हुई सांस्कृतिक एकता छिन्न-भिन्न हो गई और इसका लाभ देशद्रोही शक्तियों ने उठाया।

केंद्र की भाजपा सरकार देश को सांस्कृतिक रूप से सुदृढ़ करना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लौह पुरुष नाम से विख्यात सरदार वल्लभ भाई पटेल के 140वें जन्मदिन के अवसर पर 31 अक्टूबर, 2015 को शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' पहल की घोषणा की थी। इस योजना की प्रेरणा सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन दर्शन से ली गई है। देश की स्वतंत्रता और इसे गणराज्य बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान देश के विभिन्न राजघरानों को भारत से पृथक न होकर इसमें सम्मिलित होने के लिए तैयार किया था। उनकी सदैव से ही अभिलाषा थी कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण हो। उन्होंने आजीवन देश की एकता और अखंडता के लिए कार्य किया। उनका कहना था कि एकता के बिना जनशक्ति शक्ति नहीं है जब तक उसे ठीक तरह से सामंजस्य में ना लाया जाए और एकजुट ना किया जाए और तब यह आध्यात्मिक शक्ति बन जाती है। वे यह भी कहते थे कि यह हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह यह अनुभव करे कि उसका

देश स्वतंत्र है और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। हर एक भारतीय को अब यह भूल जाना चाहिए कि वह एक राजपूत है, एक सिख या जाट है या अन्य कुछ है। उसे यह याद होना चाहिए कि वह एक भारतीय है और उसे इस देश में हर अधिकार है, पर कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। वे कहते थे कि इस मिट्टी में कुछ अनूठा है, जो कई बाधाओं के बावजूद हमेशा महान आत्माओं का निवास रहा है।

इस योजना का उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संस्कृति, परंपराओं और प्रथाओं का ज्ञान इस रचनात्मक कदम के परिणामस्वरूप राज्यों के बीच बेहतर समझ और बंधन को बढ़ावा देना है, जिससे भारत की एकता और अखंडता में वृद्धि हो। इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संस्कृति, आदतों और परंपराओं का साझा ज्ञान राज्यों के बीच संबंध और समझ को बढ़ाकर देश की एकता और अखंडता में सुधार करना है। अंतर-सांस्कृतिक संपर्क से देश के सभी नागरिकों के बीच 'एक राष्ट्र' की भावना पैदा करने में मदद मिलेगी।

वास्तव में 'एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान' संपूर्ण देश को एक दूसरे के साथ पुनः जोड़कर एक विराट सांस्कृतिक चेतना के पुनर्स्थापना का अभियान है। भारत की सांस्कृतिक अंतर्दृष्टि स्वयं में एक बहुलतावादी विचारों की समष्टि है। यही कारण है कि एक ही भगवान राम को अयोध्या में रामलला के रूप में तो कर्नाटक में कोदंडराम अर्थात धनुषधारी के रूप में पूजा जाता है। मथुरा के कान्हा, द्वारका में द्वारकाधीश, मराठों में गर्वीले विठोवा, पुरी में जगन्नाथ जी तो राजपुताने में श्रीनाथ जी के रूप में पूजित हैं। जिस समाज ने जैसी दृष्टि से देखा वैसी ही सृष्टि का सृजन किया, यही भारतीय सांस्कृतिक चेतना की बहुलतावादी दृष्टि के एकत्व का स्वरूप है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के माध्यम से हम पुनः एक ऐसे ही समष्टि की स्थापना करने जा रहे हैं।

इस कार्यक्रम के माध्यम से एक श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना की गई है। एक ऐसे राष्ट्र के रूप में भारत के विचार का जश्न मनाना है, जिसमें विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों की विभिन्न सांस्कृतिक इकाइयां एकजुट होती हैं और एक- दूसरे के साथ बातचीत करती हैं। विविध भाषाओं, व्यंजनों, संगीत, नृत्य, रंगमंच, फिल्मों, हस्तशिल्प, खेल, साहित्य, त्योहारों, चित्रकला, मूर्तिकला आदि की यह शानदार अभिव्यक्ति लोगों को बंधन और भाईचारे की सहज भावना को आत्मसात करने में सक्षम बनाएगी। हमारे लोगों को विशाल भूभाग में फैले आधुनिक भारतीय राज्य के निर्बाध अभिन्न अंग के बारे में जागरूक करना, जिसकी मजबूत नींव पर देश की भू-राजनीतिक ताकत से सभी को लाभ सुनिश्चित होता है। विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं के घटकों के बीच बढ़ते अंतर-संबंध के बारे में बड़े पैमाने पर लोगों को प्रभावित करना, जो राष्ट्र-निर्माण की भावना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन घनिष्ठ अंतर- सांस्कृतिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से समग्र रूप से राष्ट्र के लिए जिम्मेदारी और स्वामित्व की भावना पैदा करना, क्योंकि इसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से अंतर- निर्भरता मैट्रिक्स का निर्माण करना है। एक ही समय में राष्ट्र की विविधता और एकता का जश्न मनाना है। लोगों के बीच समझ और प्रशंसा की भावना पैदा करना और राष्ट्र में एकता की एक समृद्ध मूल्य प्रणाली को सुरक्षित करने के लिए आपसी संबंध बनाना है।

'एक भारत श्रेष्ठ भारत' कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक गतिविधियां की जाती हैं। इसके अंतर्गत पांच पुरस्कार विजेता पुस्तकों और कविता, लोकप्रिय लोकगीतों का एक भाषा से भागीदार राज्य की भाषा में अनुवाद किया गया है। साझेदार राज्यों की पाक पद्धतियों को सीखने के लिए पाक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। साझेदार राज्यों से आने वाले आगंतुकों के लिए होमस्टे की व्यवस्था की गई है। पर्यटकों के लिए राज्य दर्शन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पारंपरिक पोशाक को स्वीकार करना भी इसमें सम्मिलित है। भागीदार राज्यों के साथ पारंपरिक कृषि पद्धतियों जैसी सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जा रहा है।

किसी भी भू-भाग अथवा देश की विभिन्न संस्कृतियों को एक सूत्र में बांधे रखने का कार्य आपसी प्रेम, सद्भाव एवं भाईचारे की भावना से ही संभव है। भारत में एक हजार से भी अधिक भाषाएं और बोलियां हैं। यहां कुछ कोस की दूरी पर बोली बदल जाती है। भाषाएं ही नहीं, अपितु यहां अनेक धर्म भी हैं। यहां विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। इनकी संस्कृति, सभ्यता, रीति-रिवाज, भाषा, व्यंजन, वेशभूषा आदि भी एक-दूसरे से भिन्न है, परन्तु सब मिलजुल कर रहते हैं। एक-दूसरे के त्योहारों में सम्मिलित होते हैं। ऐसा करना आवश्यक भी है, क्योंकि एक दूसरे से मिलने जुलने से ही उन्हें समझने का अवसर प्राप्त होता है। देश को श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए सभी देशवासियों का सहयोग आवश्यक है। विविधता में एकता के लिए आवश्यक है कि विभिन्न संस्कृतियों के लोग आपस में मिलजुल कर रहें। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि हम एक दूसरे की आस्थाओं एवं उनकी धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करें। जब हम सामने वाले की आस्था का सम्मान करेंगे, तो वह भी हमारी आस्था का सम्मान करेगा। ऐसा करने से आसपास में प्रेम और सद्भाव की भावना उत्पन्न होगी। सरकार की इस योजना के माध्यम से देशवासियों के मन में अपने- अपने धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्म के लोगों के प्रति भी प्रेम एवं सम्मान की भावना विकसित हो सकेगी। निःसंदेह आज के समय में ऐसी योजनाओं की अत्यधिक आवश्यकता है। ■

भारत में बेरोजगारी की समस्या का हल निकालने में मिल रही सफलता

पिछले एक दशक के दौरान केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों ने भारतीय नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई नई योजनाएं प्रारम्भ की हैं। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) प्रारम्भ की गई थी। इस योजना को प्रारम्भ करने का मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं को सुरक्षित बेहतर आजीविका प्राप्त करने के लिए उद्योग-प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना था

प्रह्लाद सबनानी

भारतीय सनातनी वेदों एवं ग्रंथो में इस बात के कई प्रमाण मिलते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि भारत सदैव ही आर्थिक रूप से सम्पन्न देश रहा है एवं भारत के समस्त नागरिकों के लिए रोजगार के भरपूर अवसर उपलब्ध रहे हैं। मुद्रा स्फीति, आय की असमानता, बेरोजगारी एवं ऋण के भारी बोझ के तले दबे रहना जैसे शब्दों का तो प्राचीन भारत के आर्थिक इतिहास में वर्णन नहीं के बराबर मिलता है। भारत के समस्त नागरिकों की पर्याप्त मात्रा में आय होती थी जिससे वह अपने परिवार का आसानी से गुजर बसर कर पाते थे एवं समाज में समस्त नागरिक प्रसन्नता पूर्वक रहते थे। दरअसल प्राचीन भारत के उस खंडकाल में नागरिकों में उद्यमशीलता अपने चरम पर थी। परिवार के जमे जमाए व्यवसाय पीढ़ी दर पीढ़ी सफलतापूर्वक आगे चलते रहते थे एवं परिवार के सदस्यों के आय अर्जन का मुख स्रोत बने रहते थे। इस दृष्टि से नागरिकों को सामान्यतः नौकरी के लिए परिवार के पारम्परिक व्यवसाय के बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। इस प्रकार उस खंडकाल में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न ही नहीं

होती थी।

भारत पर आक्रांताओं के आक्रमण एवं इसके तुरंत बाद अंग्रेजों के शासनकाल में भारतीय नागरिकों की उद्यमशीलता को समाप्त कर उनमें नौकरी करने की भावना को विकसित किया गया क्योंकि अंग्रेजों को अपने शासन को सुचारू रूप से संचालन के लिए नौकरों की आवश्यकता थी। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत की शिक्षा पद्धति को भी कुछ इस प्रकार से परिवर्तित किया गया कि भारतीय नागरिक अपनी पढ़ाई समाप्त करने के पश्चात अंग्रेजों के संस्थानों में केवल नौकरी कर सके। दीर्घकाल में इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय नागरिक केवल नौकरी को ही रोजगार का साधन मानने लगे और उन्हें यदि नौकरी नहीं मिल पाती तो वे अपने आप को बेरोजगार मानने लगे। भारतीय नागरिकों में उद्यमशीलता तो जैसे समाप्त ही हो गई थी। परंतु, पिछले लगभग 10 वर्षों के दौरान भारतीय नागरिकों में उद्यमशीलता को पुनः पैदा करने के अथक प्रयास किये गए हैं, जिनमे सफलता भी मिलती दिखाई दे रही है और भारत में अब पुनः बहुत बड़ी मात्रा में उद्यमों को स्थापित किया जा रहा है, जिससे भारतीय नागरिक अब धीरे धीरे नौकर नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बनते जा रहे हैं।

पिछले एक दशक के दौरान केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों ने भारतीय नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई नई योजनाएं प्रारम्भ की हैं। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) प्रारम्भ की गई थी। इस योजना को प्रारम्भ करने का मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं को सुरक्षित बेहतर आजीविका प्राप्त करने के लिए उद्योग-प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना था। वर्ष 2016 में स्टार्ट-अप इंडिया योजना देश में लागू की गई थी। इस योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा तंत्र विकसित करना था, जो पूरे देश में उद्यमिता का पोषण और प्रचार करता हो। वर्ष 2016 में ही स्टैंड अप इंडिया योजना प्रारम्भ की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और एससी/एसटी उधारकर्ताओं को 10 लाख रुपये तक के बैंक ऋण की सुविधा तथा ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए 1 करोड़ रु. तक का ऋण प्रदान करना था। इसके पूर्व, वर्ष 2014 में राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की स्थापना 'कौशल भारत' एजेंडे को 'मिशन मोड' में चलाने के लिए की गई थी ताकि मौजूदा कौशल प्रशिक्षण पहलों को एकजुट किया जा सके और कौशल प्रयासों के पैमाने और गुणवत्ता को गति के साथ जोड़ा जा सके। इन योजनाओं के साथ ही भारतीय नागरिकों और राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को सम्बोधित करने के लिए भारत सरकार द्वारा कई अन्य योजनाएं (पीएमगरीब कल्याण योजना, आयुषमान भारत, प्रसाद योजना, आदि) भी प्रारम्भ की गई हैं। विभिन्न सरकारों के साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे कुछ सांस्कृतिक संगठनों ने भी भारत में रोजगार के अवसर निर्मित करने के उद्देश्य से कई अन्य सामाजिक संस्थाओं को साथ लेकर भी कुछ प्रयास प्रारम्भ किया गए। संघ ने तो अपने कुछ अनुशांगिक संगठनों को यह जिम्मेदारी सौंपी कि वे इस क्षेत्र में विशेष प्रयास करें। इन सामाजिक, आर्थिक एंड सांस्कृतिक संगठनों ने मिलकर समाज में विशेष रूप से युवा नागरिकों के उद्यमशीलता को पुनः विकसित करने के सफल प्रयास किए हैं एवं अब एक बार पुनः भारत में उद्यमों को बढ़ावा मिलता दिखाई दे रहा है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में कर्मचारी भविष्यनिधि संस्थान में रजिस्टर हुए नए सदस्यों की संख्या वित्तीय वर्ष 2018-19 में 61 लाख थी जो वित्तीय वर्ष 1920-21 में 77 लाख, वित्तीय वर्ष 2021-22 में 122 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 में बढ़कर 139 लाख हो गई है। इस संख्या में लगातार सुधार से आश्य यह है कि देश में युवाओं को फोर्मल रोजगार बड़ी संख्या में मिल रहे हैं। यहां इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि इस दौरान विश्व के अन्य देशों में कई कम्पनियों में कर्मचारियों की छटनी की गई है। इसी प्रकार पीरिओडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार जनवरी 2022 से भारत में बेरोजगारी की दर में लगातार कमी देखने को मिल रही है। जनवरी 2022 में देश में बेरोजगारी की दर 8.2 प्रतिशत थी जो अप्रेल-जून 2022 तिमाही में घटकर 7.6 प्रतिशत तो वहीं जुलाई-सितम्बर 2022 तिमाही में 7.2 प्रतिशत, अकटोबर-दिसम्बर 2022 तिमाही में 7.2 प्रतिशत से घटाकर जनवरी-मार्च 2023 तिमाही में 6.8 प्रतिशत पर आ गई है। सीएमआईई द्वारा जारी एक अन्य जानकारी के अनुसार, भारत में बेरोजगारी की दर मार्च 2023 में घटकर 7.6 प्रतिशत हो गई है जो मार्च 2022 में 8 प्रतिशत एवं मार्च 2021 में 10 प्रतिशत थी।

शहरी क्षेत्रों में महिलाओं (15 वर्ष और उससे अधिक) में बेरोजगारी की दर जनवरी-मार्च 2023 तिमाही में घटकर 9.2 प्रतिशत पर आ गई है, जो कि एक वर्ष पहिले इसी तिमाही में 10.1 प्रतिशत थी। वहीं, पुरुषों में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर इस वर्ष पहली तिमाही में कम होकर 6 प्रतिशत रही, जो एक वर्ष पूर्व 2022 की जनवरी-मार्च तिमाही में 7.7 प्रतिशत थी।

देश में राज्यवार बेरोजगारी का विश्लेषण करने पर ध्यान में आता है कि 10 प्रतिशत से अधिक बेरोजगारी की दर वाले राज्य हैं, हरियाणा में 37.4 प्रतिशत, राजस्थान में 28.5 प्रतिशत, दिल्ली में 20.8 प्रतिशत, बिहार में 19.1 प्रतिशत, झारखंड में 18 प्रतिशत, जम्मू कश्मीर में 14.8 प्रतिशत, त्रिपुरा में 14.3 प्रतिशत एवं सिक्किम में 13.6 प्रतिशत है। जबकि 5 प्रतिशत के कम बेरोजगारी की दर वाले राज्य हैं ओड़िसा में 0.9 प्रतिशत, गुजरात में 2.3 प्रतिशत, कर्नाटक में 2.5 प्रतिशत, मेघालय में 2.7 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 3.1 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 3.2 प्रतिशत, छतीसगढ़ में 3.4 प्रतिशत, तेलंगाना में 4.1 प्रतिशत, उत्तराखंड में 4.2 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 4.3 प्रतिशत, तमिलनाडु में 4.7 प्रतिशत, आसाम में 4.7 प्रतिशत एवं पुडुचेरी में 4.7 प्रतिशत। विशेष रूप से मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश राज्य, जो कुछ वर्ष पूर्व तक बीमारु राज्य की श्रेणी में शामिल थे, में बेरोजगारी की दर में अतुलनीय रूप से कमी दृष्टिगोचर हुई है।

जनवरी-मार्च 2023 अवधि में देश में 45.2 फीसदी नागरिकों को रोजगार मिला हुआ है जो इससे पहले की तिमाही में 44.7 फीसदी पर था। उल्लेखनीय है कि पिछले एक दशक के दौरान भारत ने आर्थिक मोर्चे पर एक बड़ी छलांग लगाई है। स्पष्ट है कि सरकार ने अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर उसे भी संबल प्रदान करने की तमाम कोशिशें की हैं। जिसके परिणामस्वरूप, भारत में अगस्त 2023 माह में 46.21 करोड़ नागरिकों को रोजगार मिला हुआ था जबकि अगस्त 2022 में 43.02 करोड़ नागरिकों को ही रोजगार प्राप्त था, इस प्रकार एक वर्ष के दौरान 3.19 करोड़ नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। ■

आलिया भट्ट का धमाकेदार हॉलीवुड डेब्यू

जागरूक जनरक्षक

अपनी दमदार एक्टिंग से इंडियन ऑडियंस का दिल जीत चुकीं आलिया भट्ट की हॉलीवुड एंट्री भी बहुत धमाकेदार हुई है. उनकी डेब्यू हॉलीवुड फिल्म 'हार्ट ऑफ स्टोन' का ट्रेलर आ गया है. इस ट्रेलर में ही पता चल रहा है कि फिल्म में आलिया का किरदार बहुत दमदार है. पिछले साल आलिया ने अपना हॉलीवुड डेब्यू अनाउंस किया था और तभी से उनके फैन्स उन्हें इस नए स्टेज पर देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थे. 'हार्ट ऑफ स्टोन' का ट्रेलर आलिया फैन्स के एक्साइटमेंट को पूरी तरह संतुष्ट करने वाला है. जेमी डोर्नन और गैल गडोट जैसे बड़े हॉलीवुड स्टार्स के साथ आलिया, नेटफ्लिक्स की इस स्पाई थ्रिलर में जान डाल रही हैं. 'हार्ट ऑफ स्टोन' में जहां गैल गडोट और जेमी डोर्नन इंटेलीजेंस एजेंट के रोल में नजर आ रहे हैं, वहीं आलिया का किरदार फिल्म में विलेन का नजर आ रहा है. नेटफ्लिक्स का ग्लोबल इवेंट ब्राजील में चल रहा है, जिसमें 'हार्ट ऑफ स्टोन' का ट्रेलर लॉन्च किया गया. फिल्म का ट्रेलर 'वंडर वुमन' स्टार गैल गडोट से शुरू होता है, जिनके किरदार का नाम फिल्म में रेशेल स्टोन है. वो एक इंटेलिजेंस ऑर्गनाईजेशन के लिए काम करती नजर आ रही हैं, जिसके पास दुनिया का सारा डाटा है. ये इंटेलिजेंस यूनिट इस तरह से फंक्शन करती है जैसे दुनियाभर को एक तरह से कंट्रोल ही कर रही है. ट्रेलर की शुरुआत से ही गडोट कभी हवाईजहाज से कूदती, कभी पैराग्लाइडिंग करतीं तो कभी सॉलिड कॉम्बैट एक्शन करती नजर आ रही हैं. उनके साथ ही 'हार्ट ऑफ स्टोन' के मेल स्टार जेमी डोर्नन भी नजर आते हैं. ऐसा लगता है कि कहानी में दोनों का कोई रोमांटिक एंगल भी होने वाला है. जेमी भी उसी इंटेलिजेंस यूनिट से जुड़े लगते हैं, जिसमें रेशेल हैं. उनका कैरेक्टर इस तरह के लुक भी दे रहा है जैसे वो कहानी कोई बड़ा ट्विस्ट लेकर आने वाली है. ■

डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए संपर्क करे, 7007789842

http://www.darjeelingteagarden.com

डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए संपर्क करे, 7007789842

http://www.darjeelingteagarden.com